राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उतरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारित

सुरत–गुजरात,संस्करण बुधवार,14अक्टूबर2020 वर्ष–3, अंक –258 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023 (Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

तेजी से बदल रहा है मौसम, देश के इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार, IMD का अलर्ट जारी

नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र सोमवार को गहरे दबाव में बदल गया। इसके मंगलवार तड़के उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों नरसापुर और विशाखापत्तनम से गुजरने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि इसके प्रभाव के चलते मंगलवार को तेलंगाना में बेहद भारी बारिश की संभावना है जबकि कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा के दूरस्थ क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान है। उन्होंने कहा कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा और विदर्भ के दूर-दराज क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा, बंगाल की खाड़ी में कल बना कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया। इसके 13 अक्तूबर की सुबह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस दौरान, 55-65 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है, जोकि बढ़कर 75

किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार शाम से ही बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में समुद्र में हालात खराब रहेंगे। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

हाथरस घटना को लेकर दलित वोट की राजनीतिक घेराबंदी की तैयारी, BJP-कांग्रेस आमने-सामने, JDU हुई डिफेंसिव

नई दिल्ली। कांग्रेस हाथरस मुद्दे को लेकर लगातार अक्रामक है। पार्टी बिहार विधानसभा और मध्य प्रदेश उपचुनाव में इस मुद्दे पर भाजपा-जेडीयू गठबंधन को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी की कोशिश है कि 2015 की तरह इस बार भी अधिक से अधिक सुरक्षित सीट पर जीत दर्ज की जाए। इसलिए, कांग्रेस-राजद गठबंधन चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की नजर दलित मतदाताओं पर हैं। सभी पार्टियां दलितों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही हैं। यह परिणाम तय करेंगे कि हाथरस मामले का चुनाव पर कितना असर पड़ा, पर इससे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को भाजपा-जेडीयू को घेरने का मौका मिल गया है।

वहीं, लोजपा से अलग होने से आक्रामकता बढ़ी है। दलित मतदाताओं की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। इसके साथ जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने के साथ अशोक चौधरी को बिहार जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया।

भरोसा जीतने की कोशिश

जेडीयू की पूरी कोशिश है कि दलितों का उस पर भरोसा बरकरार रहे। क्योंकि, 2015 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण के बारे में दिए बयान से उन्हें 10 सुरक्षित सीट पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ वह कांग्रेस-राजद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे। इस बार भाजपा के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस और राजद हाथरस मामले को लेकर भाजपा पर अक्रामक है। पार्टी चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उठाएगी। पर सुरक्षित सीट पर पार्टी इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी। पार्टी ने दलित नेताओं को इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रचार रणनीति से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम लोजपा के साथ जेडीयू और भाजपा के व्यवहार को भी मुद्दा बनाएंगे।

बिहार में 16 फीसदी दलित–बिहार में दलित मतदाताओं की तादाद 16 फीसदी है। विधानसभा में 38 सीट आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने 14, कांग्रेस-भाजपा ने पांच-पांच और जेडीयू ने दस सीट जीती थी। बाकी सीट अन्य दलों को मिली थी। ऐसे में कांग्रेस और राजद दोनों की कोशिश होगी कि वह इन सीट पर अपना दबदबा बरकरार रखे। हालांकि, सभी दलों के लिए यह एक चुनौती है। बसपा बिहार में इस बार लोक समता पार्टी और एआईएमआईएम के मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के एक नेता ने स्वीकार किया है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बसपा कड़ी चुनौती देगी।

कश्मीर में आतंकी पैदा कर रहे धार्मिक संस्थानों पर टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का होगा प्रहार, कई स्कूल रडार पर

नई दिल्ली। कश्मीर में आतंकी पैदा कर रहे धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। शोपियां के स्कूल से जुड़े छात्रों के आतंकी संगठनों में शामिल होने की घटना सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर आसपास के जिलों के कई संस्थान हैं।

माना जा रहा कि इन्हें पाक समर्थित संगठनों से पैसा मिलता है। सूत्रों ने कहा कि टेरर मॉनीटररिंग ग्रुप के तहत कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। सैकड़ों की संख्या में धार्मिक संस्थान इनके राडार पर हैं। ये ऐसे संस्थान हैं, जो जमात की विचारधारा से प्रेरित हैं। दक्षिण कश्मीर इनके खास निशाने पर हैं।

वित्तीय स्त्रोत खंगाले जा रहे

सूत्रों ने कहा कि टीएमजी (टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप) का मुख्य काम इस तरह की गतिविधियों के वित्तीय स्त्रोत को खंगालकर उस पर प्रहार करना है। इसकी सक्रियता से ही कश्मीर में जिहादी पाठशालाओं का रहस्य सामने आ रहा है। सूत्रों ने कहा कि जमात से प्रेरित संगठन लगातार कट्टरता और

आतंक के प्रसार की कोशिश में जुटे हैं।

समन्वित तरीके से काम कर रहीं केंद्रीय एजेंसियां

माना जा रहा कि इन्हें पाक समर्थित संगठनों से पैसा मिलता है। सूत्रों ने कहा कि टेरर मॉनीटररिंग ग्रुप के तहत कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं।

टीएमजी में सीबीआई, एनआईए, ईडी, सीबीडीटी और सीबीआईसी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इन एजेंसियों के (इसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस भी शामिल है) समन्वित दृष्टिकोण से आतंकी फंडिंग पर काफी लगाम कसी गई है।

ग्राउंड वर्कर की निगरानी

पिछले साल राज्य प्रशासन ने 'फलाह-ए-आम ट्रस्ट' से जुड़े कई स्कूलों को नोटिस जारी किया और बंद करने का आदेश दिया था। एफएटी पहले जमात-ए-इस्लामी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। अब जमात और एफएटी के ग्राउंड वर्कर का डेटा तैयार करके इनकी गतिविधियों को खंगाला जा रहा है, जिससे पता लगे कि प्रतिबंध के बाद ये किन संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं।

जिहादी संस्थाओं की जड़ पर होगा प्रहार

सूत्रों ने कहा कि स्कूल बंद करने के बाद नए नाम से संचालित होने लगते हैं, इसलिए इनके स्त्रोत को काटने का प्रयास हो रहा है। पाकिस्तान से अलग-अलग तरीकों से भेजे जा रहे पैसे को एजेंसियां लगातार ट्रैक कर रही हैं। सूत्रों ने कहा कि आतंकी पाठशालाओं पर नकेल की पूरी योजना पर काम चल रहा है। जल्द ही इसके कई स्त्रोत बेनकाब किए जाएंगे।

संक्रमण के घटते दैनिक मामलों का लगातार पांचवां सप्ताह

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार भारत में बीते 5 हफ्तों से लगातार कोरोना के दैनिक मामले कम होते जा रहे हैं। एक माह बाद 9 अक्टूबर को सक्रिय मामले घटकर 9 लाख पर पहुंच गए और ये अभी और भी नीचे जा रहे हैं।

विश्वभर में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 3.74 करोड़ से अधिक हो गयी है और अब तक इस महामारी से 10.76 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में अब तक कोरोना वायरस से 37,408,593 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,076,764 लोगों की मौत हो गई है।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से जूझ रहे अमेरिका में संक्रमण से अब तक 214,771 लोगों की मौत हो चुकी है और 7,762,544 लोग संक्रमित हुये हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 66,732 नये मामले दर्ज किये गये हैं और संक्रमितों की कुल संख्या अब 71,20,538 हो गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय कोरोना के कुल 8,61,853 सक्रिय मामले हैं जबकि अब तक 61,49,535 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं।

Johnson & Johnson ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल

वाशिंगटन। दुनियाभर में कोविड-19 महामारी के कहर के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कवायद जारी है। इस बीच झटका देने वाली खबर है कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक शख्स में किसी तरह की बीमारी होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने फिलहाल अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। न्यू जर्सी कंपनी न्यू ब्रंसविक के एक प्रवक्ता जेक सरजेंट ने हेल्थ केयर न्यूज मुहैया कराने वाली एजेंसी स्ञ्ञ्ञ की रिपोर्ट को सही बताया और कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जारी ट्रायल को रोक दिया गया है।

जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। ट्रायल में हिस्सा ले रहे एक शख्स में किसी तरह की बीमारी होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने फिलहाल अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। न्यू जर्सी कंपनी न्यू ब्रंसविक के एक प्रवक्ता जेक सरजेंट ने हेल्थ केयर न्यूज मुहैया कराने वाली एजेंसी स्ञ्ञ्ञ की रिपोर्ट को सही बताया और कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वायरस की वैक्सीन पर जारी ट्रायल को रोक दिया गया है।

इस महीने की शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन बनाने वालों की शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुआ है। जॉनसन एंड जॉनसन की एडी26-सीओवी2-एस वैक्सीन अमेरिका में चौथी ऐसी वैक्सीन है, जो क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। पिछली बार की रिपोर्ट में कहा गया था वैक्सीन ने प्रारंभिक अध्ययन में कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाई है। शोधकर्ताओं ने कहा था कि अब तक के परीक्षण परिणामों के आधार पर कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं थे।

जॉनसन एंड जॉनसन ने जब इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण को शुरू किया था, तब कंपनी ने कहा था कि इसके तहत अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और पेरू में 60 हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगने की खबर ऐसे वक्त में आई है, जब इससे पहले एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी गई थी।

वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सबसे आगे चल रही थी, मगर बीते दिनों कुछ वालंटियर की कोविशील्ड टीका लेने के बाद हालत बिगड़ने पर तीसरे चरण के परीक्षण छह सितंबर को रोकने पड़े थे। हालांकि, ब्रिटेन और भारत में दोबारा शुरू हो चुके हैं। जबकि, अमेरिका या अन्य देशों ने अभी दोबारा मंजूरी नहीं दी।

69000 शिक्षक भर्ती

31661 की जगह 31277 पदों पर ही भर्ती, 14-15 अक्टूबर को काउंसिलिंग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31277 सहायक अध्यापकों के पदों के लिए मेरिट सूची जारी कर दी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 14-15 अक्टूबर को होगी। नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। ये जानकारी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा सतीश चन्द्र द्विवेदी ने दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 69000 शिक्षक भर्ती में 31277 पदों पर भर्ती की जा रही है। पहले चरण में अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31277 पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। डा. द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा 31277 अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है। हालांकि खबर पब्लिश करने के वक्त यह वेबसाइट खुल नहीं रही है। चयनित अभ्यर्थियों में 15933 अनारक्षित श्रेणी, 8513 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6615 अनुसूचित जाति एवं 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यथी हैं। चयन एवं नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

31661 की जगह 31277 पदों पर ही भर्ती–सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका राम शरण मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 21 मई को और सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 9 जून, 2020 को पारित आदेश के तहत ये चयन की कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 69000 पदों में से 37339 पदों को शिक्षामित्रों के लिए होल्ड करते हुए बाकी पदों पर भर्ती के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने 24 सितम्बर को आदेश जारी करते हुए 31661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन एससी वर्ग में कम अभ्यर्थी पात्र होने के कारण केवल 31277 पदों पर ही चयन प्रक्रिया की जा रही है।

कांग्रेस के CEA पैनल की बैठक आज, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर भी होगी चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस के नवगठित केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण (सीईए) की कोरोना महामारी के बीच अगले कुछ महीनों में संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए बुधवार यानी आज बैठक होगी। इस मामले से जुड़े लोगों ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में सभी राज्य इकाइयों से प्रतिनिधियों की अपडेटेड लिस्ट भेजने के लिए कहा था।

नाम नहीं छापने की शर्त पर कांग्रेस के एक अधिकारी ने कहा कि सीईए ने पार्टी के डेटा और प्रौद्योगिकी विभाग से एआईसीसी सदस्यों के विवरण को सत्यापित करने में मदद करने के लिए भी कहा है।

अध्यक्ष के चुनाव पर होगी चर्चा–उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में बुधवार को होने वाली बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की आधारशिला रखी जाएगी और कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) भी शामिल होगी।

11 सितंबर को एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल को अंजाम देते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष

24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने एक महीने के भीतर संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय से कहा था,

सोनिया गांधी ने आंतरिक चुनाव कराने के लिए सीईए का गठन किया था। पांच सदस्यीय सीईए का नेतृत्व मधुसूदन मिस्त्री कर रहे हैं और इसके सदस्य राजेश मिश्रा, कृष्णा बायर गौड़ा, एस जोथिमणि और अरविंदर सिंह लवली हैं, जो पिछले महीने सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों में हैं।

24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने एक महीने के भीतर संगठनात्मक चुनाव कराने के लिए पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय से कहा था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद सहित कुछ सदस्यों ने कहा कि महामारी के कारण संभव नहीं है। अंत में, आंतरिक चुनावों को पूरा करने के लिए छह महीने की ऊपरी सीमा तय की गई। हैदराबाद स्थित राजनीतिक विश्लेषक सी नरसिम्हा राव ने कहा कि संगठनात्मक चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं। उन्होंने कहा, ÷कांग्रेस में, नामांकन कई दशकों से एक अभिन्न अंग बन गया था। किसी भी पार्टी पद के लिए चुनाव कराना अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंतरिक चर्चा की प्रक्रिया को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

ताकि मांग बढ़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की, वह लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने की एक और कवायद है। ये व्यावहारिक कदम हैं, और इनसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के बढ़ने की उम्मीद बांधी जा सकती है। इन सुविधाओं के तहत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को दस हजार रुपये की करमुक्त राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी और कर्मचारी इसे 31 मार्च तक किसी भी त्योहार में खर्च कर सकेंगे। उन्हें दस किस्तों में इसे लौटाने की सुविधा होगी। इसी तरह, 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' में कर्मचारी 'रिइंबर्समेंट' की बजाय सीधे नकदी का दावा कर सकेंगे और इस राशि का इस्तेमाल भी उन्हें 31 मार्च से पूर्व कर लेना होगा। अपने कर्मचारियों के अलावा केंद्र ने राज्यों को भी पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का एलान किया है। राज्य 31 मार्च तक अपनी नई-पुरानी योजनाओं पर इसे खर्च कर सकेंगे और उनके पास अगले 50 वर्षों में इसे चुकाने की सहूलियत होगी। सरकार का आकलन है, जो तर्कसंगत भी है कि इन कदमों से बड़ी मांग पैदा होगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम देशी-विदेशी वित्तीय व रेटिंग संस्थाओं के जो आकलन हैं, वे सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी हैं। हालांकि, अनलॉक की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद बाजार में स्थितियां कुछ सुधरी हैं, खुद वित्त मंत्री ने भी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार की स्थिति पर संतोष जताया है। लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है कि बाजार में मांग बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापसी मुमकिन नहीं है। और मांग बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के जेहन से महामारी से जुड़ी आशंकाएं तिरोहित हों और वे खुलकर खर्च करने की स्थिति में आएं। लॉकडाउन ने मध्यवर्ग को किफायती खर्च के लिए बाध्य किया है और जब तक कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां सामान्य के करीब नहीं पहुंचेंगी, सामाजिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका पूर्व स्थिति में लौटना कठिन है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की अहमियत समझी जा सकती है।

दुनिया भर के कई अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उसे गरीबों की जेब में कुछ अरसे तक पैसे डालने पड़ेंगे, ताकि बाजार में मांग की स्थिति सुधरे। उनका जोर खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा करने पर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने की इसकी क्षमता असंदिग्ध है। कोरोना-काल ने तो इसके प्रामाणिक आधार भी मुहैया कराए हैं। जब सभी क्षेत्रों की विकास दर जमीन पर लेट रही थी, तब कृषि क्षेत्र देश को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा था। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ठोस क्षमताओं को देखते हुए ही मनरेगा का बजटीय आबंटन बढ़ाया है। भारत में त्योहार अर्थव्यवस्था को मजबूत संबल देते हैं। यही वक्त होता है, जब खासतौर से ग्रामीण लोग दैनिक जरूरतों के आगे की खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देते आए हैं। कोरोना ने इस साल के त्योहारों का रंग फीका कर दिया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के उड़े रंग इन्हीं की बदौलत सुर्खरू भी होंगे। सरकार को कुछ और राहतें असंगठित क्षेत्रों पर भी बरसानी होंगी।

बलात्कार के विरुद्ध

गृह मंत्रालय ने अपराधों विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एड़वाइजरी जारी की है। इतमें कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए राज्यों से कहा गया है कि वे इनका कड़ाई से अनुपालन कराएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि दुष्कर्म की शिकायत पर निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में जांच दो महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंड़ात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जो जांच प्रक्रिया को बाधित करते हैं। वास्तव में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों में गृह मंत्रालय समय-समय पर इस तरह की एड़वाइजरी करता रहता है। हाथरस कांड़ के बाद उसने फिर से एड़वाइजरी जारी की है। इन दिनों हाथरस कांड़ को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कठघरे में खड़ी कर रही है। प्रदेश सरकार की मांग पर सीबीआई इस कांड़ की जांच कर रही है। वस्तुतः महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में समस्या कानून में नहीं कानून के अनुपालन और क्रियान्वयन में है। महिला अपराधों के संबंध में जो कानून है वे पर्याप्त तौर पर कठोर हैं। बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट के लागू होने के बाद कानून की कठोरता और बढ़ गई है, लेकिन वास्तविक समस्या कानून को लागू करने वाली व्यवस्था और भारतीय समाज की विभिन्न दुष्प्रवृत्तियों की है। जब तक महिलाओं के संबंध में व्यापक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी और सामाजिक विसंगतियों को दूर कर समाज व्यवस्था को महिला सुरक्षा के अनुकूल नहीं बनाया जाएगा तथा जब तक पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक चाहे कोई भी एड़वाइजरी जारी किया जाए उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। कोई भी कठोर कानून तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि न्याय तंत्र और पुलिस तंत्र की सक्षमता पूरी तरह उके अनुकूल न हो। साथ ही अपराध की गंभीरता राजनीतिक, सामाजिक और जातीय विभाजनों से तय न हो, जैसा कि हाथरस के मामले में देखने को मिल रहा है।

टू दि प्वाइंट/आलोक पुराणिक

हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं

पाकिस्तान में गेहूं साठ रुपये किलो बिक रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान कह रहे हैं कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है।

भारत इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, यह बात पाक हुक्मरान साफ तौर पर नहीं बता पा रहे हैं, पर इस हालत के लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान मजे का मुल्क है, गेहूं महंगा हो जाए, तो भारत जिम्मेदार है। आतंक बढ़ जाए, तो सरकार कहती है कि हमारे हाथ में क्या है, देश तो आर्मी चला रही है। आर्मी से पूछा जाए, तो आर्मी कहती है कि जी हम कौन-मुल्क में चुनी हुई सरकार है, सारी जिम्मेदारी उसी की।

मुल्क में चुनी हुई सरकार को बताया जाए कि चलाने वाले तो आप। तो चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे खुद पर हंसते हैं और खुद से ही पूछते हैं अच्छा हम कब से चला रहे हैं देश। हमें तो ना पता कि हम देश चला रहे हैं। फिर एक दिन पता चलता है कि पाकिस्तान में सब कुछ चीन वाले चला रहे हैं। गंगाधर ही शक्तिमान है और चीन ही पाकिस्तान है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जिम्मेदारी बस इतनी है कि वह पूरी जिम्मेदारी से यह बता दें कि उन्हे छोड़कर मुल्क में कौन है जिम्मेदार, हालात का। नवाज शरीफ ने बताया कि मुल्क में चुनी हुई सरकार से ऊपर एक सरकार चलती है-आर्मी की। गोया यह बात वह पहले नहीं जानते थे। पाकिस्तान में जो सेना की मदद से सरकार बनाता है और चलाता हैग वह ऐसा ही दिखाता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है। पाकिस्तान में लोकतंत्र है, यह सुनकर पाक सेना के जनरल हंसते हैं। पाकिस्तान में सरकार के विरोध की कमान उस मौलाना के हाथ में थमा दी गई है, जिन पर आरोप हैं कि वह पाकिस्तान में आतंकियों का समर्थन करते हैं।

आतंकियों का समर्थन ना करने की शर्त हो, तो पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान नहीं हो सकता। इमरान खान से लेकर सेना तक सब आतंकियों के समर्थन से ही खेल चलाते हैं। पर इस खेल का जिम्मेदार कौन है। चीन है जी, तो चीन की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। वह नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो लोकतांत्रिक देश है जी।

तमिल भूमि पर भाजपा की उलझन

एस श्रीनिवासन

पिछले हफ्ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का टिकट पाने में सफल रहे। तमिलनाडु में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बेशक उन्हें अन्नाद्रमुक के 90 फीसदी विधायक दल का समर्थन हासिल है, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी और कैबिनेट में दूसरे नंबर के कद्दावर नेता ओ पन्नीरसेल्वम भी इस क्रम में अच्छी-खासी सौदेबाजी करने में कामयाब रहे। पन्नीरसेल्वम की मुख्य मांग थी, एक ऐसी रणनीतिक कमेटी का गठन, जो पार्टी का कामकाज देख सके। वह न सिर्फ इस कमेटी में अपने समर्थकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने में सफल रहे, बल्कि चुनाव में अपनी पसंद के कम से कम 50 फीसदी उम्मीदवारों को भी अब वह उतार सकेंगे।

मगर पलानीसामी का सिरदर्द तो अभी शुरू हुआ है। उन्हें चुनाव हारने की सूरत में पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति पर तो सोचना ही होगा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उम्मीदवारी को सहयोगी दलों का भी साथ मिले, क्योंकि उनके समर्थन के बिना विपक्ष की चुनौतियों का वह शायद ही सामना कर सकेंगे। जे जयललिता के बाद अन्नाद्रमुक पार्टी उनके नेतृत्व में उस तरह मजबूत नहीं रह सकी है। जयललिता ने तो राज्य पर एकछत्र राज किया था और 2014 का लोकसभा चुनाव अपने बूते लड़ा था। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं किया। यदि त्रिशंकु संसद बनी, तो उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी घोषित किया था। तब वह रणनीति कामयाब रही थी और सूबे की 39 लोकसभा सीटों में से 37 पर उन्हें जीत मिली। भाजपा ने अपना अलग गठबंधन बनाया था, लेकिन वह चुनाव में बुरी तरह नाकाम रहा था।

जयललिता के निधन के बाद, 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा ने अन्नाद्रमुक का नेतृत्व मान तो लिया, मगर पांच लोकसभा सीटों पर लड़ने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। अब वह सब कुछ बदलने को उत्सुक है, और इसीलिए आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी शर्तों पर गठबंधन बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए यह दावा भी कर रही है कि राज्य में उसके लिए काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।

राज्य में भाजपा के अलावा पीएमके, एमडीएमके और टीएमसी अन्नाद्रमुक की मुख्य सहयोगी पार्टियां हैं। इनमें से भाजपा सबसे शक्तिशाली घटक है, क्योंकि केंद्र की चाबी उसी के पास है। ऐसे में, अन्नाद्रमुक शायद ही उसका विरोध कर सकती है। मगर उसे अपने रिश्ते को परिभाषित करने के लिए एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा को उत्तर भारत की एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है, जो अपने क्षेत्रीय सहयोगी पर दबदबा हासिल करना चाहती है। ऐसे में, छोटी-सी गलती से भी मतदाताओं के सामने अन्नाद्रमुक की स्थिति असहज हो सकती है। मगर विकास संबंधी कामों में केंद्र के साथ के लिए उसे इस पार्टी की जरूरत भी है।

पलानीसामी के लिए बुरी खबर यह है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भाजपा ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था। राज्य के भाजपा नेताओं ने कहा है कि अन्नाद्रमुक ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है, एनडीए गठबंधन का नहीं। जाहिर है, भाजपा अपने विकल्पों का विस्तार करना चाहती है। वह पीएमके, टीएमसी, डीएमडीके और रजनीकांत की राजनीतिक पार्टी के साथ, जिसका अभी तक गठन नहीं हुआ है, गठजोड़ कर सकती है। मगर ये कोई आसान विकल्प नहीं हैं। पीएमके अंबुमणि रामदास के रूप में अपना मुख्यमंत्री-उम्मीदवार उतारना चाहती है। चूंकि इस पार्टी के पास छह से सात फीसदी वोट हैं, लिहाजा वह सौदेबाजी कर सकती है। वहीं, रजनीकांत ने बेशक मुख्यमंत्री की अपनी दावेदारी खारिज कर दी है, लेकिन चुनाव महज छह महीने दूर हैं और उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसके कारण भाजपा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। डीएमडीके की भी अपनी समस्याएं हैं। भले ही सर्वश्रेष्ठ दिनों में इस पार्टी ने 10 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए हैं, लेकिन अभी यह लोकप्रियता के मामले में जमीन पर है। इसके नेता विजयकांत बीमार हैं और उनका अस्पताल आना-जाना लगा रहता है। इसीलिए अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सबसे अच्छा दांव है। मगर बातचीत की मेज पर आने से पहले वह अन्नाद्रमुक के मुख्यमंत्री पद के दावेदार को समर्थन देने के नाम पर उसे अपनी शर्तों पर राजी करना चाहती है। अन्नाद्रमुक पार्टी भी, जो अब प्रभावी रूप से पलानीसामी के नेतृत्व में है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। उसके एक वरिष्ठ नेता ने घोषणा की है कि जो दल पलानीसामी का नेतृत्व मानेंगे, सिर्फ वही गठबंधन के लिए संपर्क करें। पार्टी नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि उसके कैडर और समर्थक किसी बाहरी का वर्चस्व कतई स्वीकार नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा परोक्ष रूप से अन्नाद्रमुक पर हावी होने की कोशिश करेगी। मगर इसमें सफलता संदिग्ध है, क्योंकि पलानीसामी व पन्नीरसेल्वम आपसी समझौतों से एकमत हो गए हैं। दोनों नेताओं को एक-दूसरे की जरूरत है, क्योंकि दोनों का पार्टी के परंपरागत वोट-बैंक पर पूरा अधिकार नहीं है। पलानीसामी गोंडर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसका राज्य के पश्चिमी हिस्से में मजबूत आधार है, जबकि पन्नीरसेल्वम थेवर समुदाय से, जिसकी सूबे के दक्षिणी हिस्से में दमदार उपस्थिति है। ये दोनों समुदाय अन्नाद्रमुक की रीढ़ हैं और इनमें से कोई भी अगर खिसका, तो पार्टी को काफी नुकसान होगा। ये दोनों नेता शशिकला नटराजन से आने वाले किसी आसन्न खतरे को टालने के लिए भी साथ रहना चाहेंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह जनवरी में जेल से रिहा हो सकती हैं।

साफ है, पलानीसामी और पन्नीरसेल्वम, दोनों राजनीतिक सच्चाई को समझते हैं, इसीलिए निजी स्वार्थ के तहत साथ-साथ रहेंगे। वैसे, राज्य में चुनावी अंकगणित और वोटरों की प्रकृति ऐसी रही है कि जयललिता और करुणानिधि जैसे मजबूत नेता भी विधानसभा चुनावों में गठबंधन किया करते थे। मगर तब एकमात्र अंतर यह था कि गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए वे पर्याप्त ताकतवर थे। आज बदली परिस्थितियों में कमान पर किसी और का कब्जा भी हो सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

> भाजपा अन्नाद्रमुक पर हावी होने की कोशिश कर सकती है, मगर इसमें सफलता संदिग्ध है, क्योंकि पलानीसामी व पन्नीरसेल्वम एक हो गए हैं।

गृह मंत्रालय का परामर्श

जमीनी हकीकत बदलने में बरतें ईमानदारी

अनूप भटनागर

हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या की घटना से देश भर में उभरे आक्रोश के बाद एक बार फिर औपचारिकता निभाते हुए मामले की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने का परामर्श जारी किया गया है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में हैदराबाद व उन्नाव में बलात्कार पीड़ित को जिन्दा जलाये जाने की घटना के बाद भी इसी तरह का सख्त रुख अपनाया था। इस बार गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये परामर्श जारी किया है जबकि पिछले साल दिसंबर में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी ऐसे मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करने पर जोर देते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे।

अब हाथरस कांड के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अनिवार्य कार्रवाई करने और ऐसे मामलों की जांच दो महीने में पूरी करने तथा मृत्यु के समय दिये गये बयान को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करने के लिये कहा है कि वह मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं किया गया है।

इसे विडंबना ही कहा जायेगा कि 2018 में कानून में संशोधन के माध्यम से पहले ही यह प्रावधान किया जा चुका है कि बलात्कार की घटनाओं की जांच का काम दो महीने के भीतर पूरा करना होगा लेकिन अक्सर देखा गया है कि जांच अधिकारी या जांच एजेन्सियां इस अवधि में अपनी जांच पूरी नहीं कर पाते हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है। दरअसल यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर कारगर तरीके से अंकुश लगाने के लिये जनता और राजनीतिक दलों के दबाव में कानून तो बन गया लेकिन कानून में इस प्रावधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जरूरतों की ओर गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया गया।

यही वजह है कि आज भी देश में इस तरह के अपराधों की जांच के लिये पर्याप्त संख्या में अपराध विज्ञान प्रयोगशालायें नहीं हैं। जो प्रयोगशालायें हैं, उनमें पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दो महीने के भीतर जांच पूरी करने के कानूनी प्रावधान और गृह मंत्रालय के परामर्श की गंभीरता की सहज ही कल्पना की जा सकती है।

वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद 2013 में कानून में प्रावधान किया गया कि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दो महीने में ऐसे मुकदमों की सुनवाई पूरी करनी होगी और इसके लिये त्वरित अदालतें गठित की जायेंगी। लेकिन क्या आरोप पत्र दाखिल होने के बाद दो महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो रही है। कानून में कठोर सजा और शीघ्र न्याय का प्रावधान करने के बाद सरकार यह मान लेती है कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी। लेकिन कानूनी प्रावधानों के अमल के मामले में अक्सर ढुलमुल रवैया अपनाया जाता रहा है और अंत में न्यायपालिका को ही इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है।

इसी कानून में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिये विशष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया गया लेकिन छह साल बाद 2019 में गांधी जयंती के अवसर पर 1023 विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करने का काम शुरू किया गया। यह भी केंद्र-राज्यों की उदासीनता के बाद शीर्ष न्यायालय की सख्ती की वजह से संभव हो पाया। न्यायालय की बदौलत ही यह भी संभव हुआ कि इन 1023 त्वरित अदालतों में से 389 अदालतें सिर्फ बच्चों के यौन शोषण के अपराध से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करेंगी।

किशोरियों के साथ यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर उच्चतम न्यायालय ने कई बार सरकार को आड़े हाथ लिया और जानना चाहा कि पोक्सो कानून के तहत मुकदमों की सुनवाई के लिये पर्याप्त संख्या में त्वरित अदालतें क्यों नहीं हैं? देश में पर्याप्त संख्या में अपराध विज्ञान प्रयोगशालायें क्यों नहीं हैं? न्यायालय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर जुर्माना भी कर चुका है। इस समय हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, नयी दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल और पुणे में केन्द्रीय फारेंसिक साइंस प्रयोगशालायें हैं जबकि राज्य सरकारों के अंतर्गत भी करीब 30 फारेंसिक साइंस प्रयोगशालायें है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इन प्रयोगशालाओं की कम संख्या पर चिंता व्यक्त कर चुका है, जिसकी वजह से सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट समय पर नहीं मिलती है जो मुकदमों की सुनवाई में विलंब का एक बड़ा कारण बन जाती है। यदि सरकार मामले में गंभीर है तो उसे त्वरित अदालतों की संख्या बढ़ाने के साथ ही इसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी। इससे पहले, सरकार को जांच व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही फारेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ानी होगी तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा प्रयोगशालाओं में चिकित्सकों और दूसरे कर्मचारियों का कोई भी पद रिक्त नहीं रहे।

नशाखोरी

सख्त कार्रवाई की दरकार

अजय कु. मिश्रा

देश की कई मुख्य समस्याओं में बड़ी समस्या देश में नशा करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा होना है।

खासकर युवाओं का इसमें तेजी से शामिल होना। नशे के सेवन से व्यक्तिगत बीमारियों, आर्थिक तंगी के साथ-साथ पारिवारिक विघटन, नैतिक मूल्यों का पतन, अपराध में वृद्धि होना आम बात है। आज कई बड़े अपराध के पीछे नशे का सेवन होना पाया जाता है। इस नशे की वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है वही अमीर लोगों के शौक में यह नशा शान से कम नहीं है। पारिवारिक विघटन, औरतों, बच्चियों के प्रति यौन हिंसा में भी वृद्धि हो रही है। बॉलीवुड की वर्तमान घटना ने नशे की पहुंच को हर स्तर पर होना पुन- जागृत किया है।

देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक गांव तक नशे का कारोबार किसी-न-किसी रूप में मौजूद है। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश राज्यों में नशाखोरी अपनी गहरी पैठ बना चुका है। विभिन्न स्वरूपों में जैसे शराब, देशी शराब, कैनिबस (भांग,गांजा, चरस,धतूरा) ओपिओइड ड्रग्स (हेरोइन, अफीम, अन्य फार्मास्यूटिकल ड्रग्स), सेडेटिव, हिप्नोटिक, नशीली दवाओं को इंजेक्शन द्वारा नसों में लगाना, उत्तेजक पदार्थ, नार्कोटिक/स्वापक, निकोटिन यह उपलब्ध है। व्यक्तिगत बजट के अनुरूप हर श्रेणी में नशा उपलब्ध है। हर तबके के लिए अलग-अलग नशा आज मौजूद है, जिसका कारोबार भी खूब फल-फूल रहा है। फाइनेंसियल एक्सप्रेस ने नशा करने को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें 186 जिलों के दो लाख घरों के 5 लाख लोगों को शामिल किया गया था। इस सर्वे की रिपोर्ट फरवरी 2019 में प्रकाशित की गई थी। इसके अनुसार 123 जिलों में लगभग 10 हजार लोग प्रतिबंधित नशे का सेवन करते पाए गए थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि भारत में, इटली सहित विश्व के 112 देशों की, कुल आबादी से अधिक, छह करोड़ लोगो में शराब की लत है यानी यह 6 करोड़ शराबियों का यह घर है। इनमें से 3.2 करोड़ लोगों में शराब की लत है। 3.1 करोड़ से अधिक लोग कैनिबस (भांग, गांजा, चरस, धतूरा) का सेवन करते हैं। एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के अनुसार देश में 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं। नशे के सेवन में महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि उनकी संख्या काफी कम है पर दिन-प्रतिदिन उनकी भी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। खिलाड़ी, अभिनेता, व्यवसायी, कर्मचारी, नेता, छात्र, किसान, मजदूर, यहां तक की कुछ राज्यों में महिलाओं के जीवन का अभिन्न हिस्सा नशा बन गया है। इसमें वृद्धि के पीछे कई कारण हैं पर सरकार की दोहरी नीति भी नशाखोरी को बढ़ावा देती है। कोरोनाकाल में शराबों की दुकानों का खोला जाना इसका जीवंत प्रमाण है। कई राज्यों का आर्थिक बजट भी इन नशें के व्यापार पर टीका हुआ है। ऐसे में कई मनकों, प्रक्रियाओं, और सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है अन्यथा की परिस्थिति में सरकार की आय में वृद्धि होती रहेगी। परन्तु युवा गुमराह होता रहेगा, जिससे अपराध, अवसाद, आत्महत्या, भेदभाव, महिला अपराध को बढ़ावा मिलेगा। सरकार लाभ-हानि के अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाना अत्यंत जरूरी है और यह तभी संभव हो सकेगा, जबकि नशा के खिलाफ लोग एकजुट हो। ड्रग्स का धंधा पूरी दुनिया में फैला है और भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी सप्लाई में अहम भूमिका निभाती है। भारत हेरोइन और हशीश का उत्पादन करने वाले देशों के बीच में स्थित है। गोल्डन ट्रायंगल (थाइलैंड-लाओस-म्यांमार) और गोल्डन क्रीसेंट (अफगानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) के कई देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं। इसकी वजह से भारत में ड्रग्स को पहुंचाना आसान हो जाता है। वैसे तो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार देश में हर साल करीब 10 लाख करोड़ रु पये का ड्रग कारोबार किया जाता है। यह आकलन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई ड्रग्स और सूचना के आधार पर किया गया है।

आज के समय में नशे के प्रति सामान्य कार्रवाई, जागरूकता बढ़ाने की नहीं बल्कि कठोर एक्शन की जरूरत है। पूर्ण प्रतिबंध के साथ-साथ स्कूली सिलेबस में नशे के दुष्प्रभाव को शामिल किया जाए, जिससे आगामी पीढ़ी इसके नुकसान को समझ सके और भविष्य में दुनियां के किसी कोनों में होने पर भी इससे दूरी बनाने में सफल भी हो सकें। जब तक ड्रग्स की मांग रहेगी, आपूर्ति होती रहेगी। ड्रग के अवैध कारोबार में मुनाफा बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार को सबसे पहले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कृषि सुधार अनाज उत्पादक राज्यों के लिये बेहतरः एसबीआई अर्थशास्त्री

मुंबईः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को कहा कि हाल में कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार अनाज उत्पादक राज्यों की जरूरतों को पूरा करता है और इस लिहाज से यह कुछ हद तक संकीर्ण सोच पर आधारित जान पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे केवल परंपरागत खेती को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि हाल में संपन्न संसद के मानसून सत्र में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन विधेयकों को मंजूरी दी गयी। इसका मकसद कृषि उपज के विपणन, बिक्री में बदलाव लाना तथा भंडारण सीमा को समाप्त करना है। एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों ने विधेयकों का स्वागत करते हुए कहा कि इन विधेयकों में जो उपाय किए गए, उसकी जरूरत थी लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारा देश केवल अनाज ही उपजाने वाला नहीं रह गया है बल्कि दूसरे राज्य विभिन्न फसल पैदा कर रहे हैं। इस बारे में एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष ने कहा, ''हम केवल अनाज पैदा करने वाले नहीं रह गए हैं और यह समय श्वेत क्रांति का है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के पक्ष में है जिन्होंने हरित क्रांति की अगुवाई की लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादक राज्यों की उपेक्षा करता है।

कांग्रेस सांसद का भारत-पाकिस्तान, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार फिर शुरु करने का आग्रह

नयी दिल्ली, अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत का पाकिस्तान और अन्य पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने मोदी से ऐसी नयी व्यापार नीति लाने के लिए भी कहा जो कोविड-19 के बाद की दुनिया में ज्यादा स्वीकार्य हो। मोदी को लिखे पत्र में औजला ने भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार फिर शुरू करने के लिए कहा। विश्वबैंक के मुताबिक इन दोनों देशों के बीच 37 अरब डॉलर के व्यापार का अनुमान है। हालांकि अभी यह 2.5 अरब डॉलर वार्षिक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कृषि और आर्थिक पुनर्जागरण की नयी शुरुआत के लिए उनकी प्रधानमंत्री कार्यालय से दरख्वास्त है कि वह व्यापार फिर शुरू करने के लिए राजनयिक पहल करें। साथ कोविड के बाद की दुनिया में स्वीकार्य नहीं व्यापार नीति लाएं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में लगाये गए 200 प्रतिशत के सीमाशुल्क के चलते अमृतसर जैसे सीमायी शहर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

सरकार ने कृषि रसायन उद्योग से नये कीटनाशक रसायन प्रस्तुत करने को कहा

नयी दिल्ली, सरकार ने मंगलवार को कृषि रसायन उद्योग को किसानों के लाभ के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप औषधीय रसायन उतारने का आह्वान किया, जबकि उद्योग निकाय क्रॉपलाइफ इंडिया ने इस क्षेत्र की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर नीति और नियामकीय व्यवस्था कायम करने पर जोर दिया। कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस उद्योग पर एक वीडियो सम्मेलन में , ''फसल संरक्षण उद्योग को किसानों के लाभ के लिए नए, सुरक्षित और अधिक प्रभावी उत्पाद लाने की जवाबदेही को साझा करने के लिए आगे आना चाहिये।'' उद्योग निकाय द्वारा जारी एक बयान में मंत्री के हवाले से कहा गया है कि भारतीय कृषि रसायन उद्योग एक सफल क्षेत्र है और वह सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और नियामक सुधारों के साथ खुद को जोड़ने के लिए खुले विचार के साथ पूरी तरह से तैयार है। रूपाला ने कहा कि सरकार, किसानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक 'संकुल' वाला दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने उद्योग जगत से इस पहल का समर्थन करने को कहा। इस अवसर पर बोलते हुए, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के सीईओ अशोक दलवई ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार बनाने की जरूरत है क्योंकि इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए देश में एक ठोस बुनियादी ढांचा और नियामक प्रणाली मौजूद है।

आरबीआई ने छोटे कारोबारियों को दिया तोहफा, कर्ज सीमा बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए की

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए खुदरा ऋण सीमा बढ़ाकर 7.5 कररोड़ रुपए कर दी। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। इस पहल का मकसद छोटी कंपनियों के लिए कर्ज प्रवाह बढ़ाना है।

कंपनियों को बैंक से मिलेगा 7.5 करोड़ रुपए का कर्ज

आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 75 प्रतिशत जोखिम भारांश सभी नए कर्ज और मौजूदा ऋण पर लागू होगा। इसके तहत कंपनियां बैंक से 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक और कर्ज ले सकेंगी। इसमें कहा गया है पचास करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले व्यक्तिगत और छोटी कंपनियों के लिए कर्ज की लागत में कमी लाने और बासेल दिशानिर्देश के अनुरूप करने के लिए, सकल खुदरा कर्ज के लिए 5 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया गया है।

नौ अक्टूर को हुई घोषणा

इससे पहले, मौद्रिक नीति सिमिति की बैठक के बाद नौ अक्टूर को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की थी। एक अन्य अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि एक सितंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक एसएलआर (सांवधिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियों के लिए 'हेल्ड टू मैच्युरिटी' (परिपक्व होने तक प्रतिभूति रखना) के तहत बढ़ी हुई सीमा 22 प्रतिशत की व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक रखने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। बैंक अब इस प्रकार की अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी में 31 मार्च, 2022 तक रख सकती हैं। आरबीआई ने यह भी निर्णय किया है कि बढ़ी हुई एचटीएम सीमा को 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही से चरणबद्ध तरीके से 19.5 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाएगा।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आवासीय परियोजना के लिए बेंगलुरु में 15 एकड़ जमीन खरीदी

नयी दिल्ली. गोदरेज प्रॉपर्टीज ने आवासीय परियोजना के विकास के लिए बेंगलुरु में 15 एकड़ जमीन का टुकड़ा खरीदा है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसने बेंगलुरु के सरजापुर में 15 एकड़ जमीन खरीदने के लिए सौदा किया है। गोदरेज समूह की इकाई गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस सौदे के मूल्य का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने यह जानकारी भी नहीं दी है कि उसने यह जमीन किससे खरीदी हैं। कंपनी ने कहा कि 15 एकड़ में फैली इस परियोजना के तहत करीब 16 लाख वर्ग फुट बिक्रीयोग्य क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें विभिन्न आकार के आवासीय अपार्टमेंट होंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा, ''बेंगलुरु हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण बाजार है। यह हमारी देश के प्रमुख रीयल एस्टेट बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति के अनुकूल है।''

विप्रो की 9,500 करोड़ रुपये की शेयर पुनर्खरीद योजना को बोर्ड की मंजूरी

नयी दिल्ली. आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विप्रो के निदेशक मंडल ने 400 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 9,500 करोड़ रुपये की शेयर पुनर्खरीद योजना को मंगलवार को मंजूरी दी । इससे एक सप्ताह पहले विप्रो की प्रतिद्वंद्वी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने 3,000 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 16,000 करोड़ रुपये की पुनर्खरीद योजना की घोषणा की थी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में विप्रो ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने 400 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 23.75 करोड़ इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी पुनर्खरीद पर 9,500 करोड़ रुपये तक खर्च करेगी। । यह 30 सितंबर, 2020 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 4.16 प्रतिशत के बराबर है। बीएसई में मंगलवार को कंपनी का शेयर भाव 375.5 रुपये पर बंद हुआ। इस तरह पुनर्खरीद इसकी तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक मूल्य पर की जाएगी। विप्रो के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) जतिन दलाल ने एक बयान में कहा कि पहली छमाही में कंपनी के पास देनदारी मुक्त नकद धन (मुक्त नकदी) शुद्ध लाभ के 160.7 प्रतिशत के बराबर थी। उन्होंने कहा, ''शेयर पुनर्खरीद की घोषणा शेयरधारकों को मजबूत प्रतिफल प्रदान करने के हमारे सिद्धान्त के अनुरूप है।'' पिछले साल विप्रो ने 325 रुपये प्रति शेयर मूल्य पर 32.31 करोड़ शेयरों की पुनर्खरीद की थी।

कोविड-19 के प्रभाव से उबरी चीन की अर्थव्यवस्था, सितंबर में निर्यात 9.9 प्रतिशत बढ़ा

बीजिंग।

चीन की अर्थव्यवस्था अब कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से उबरती दिख रही है। सितंबर में चीन के व्यापार के आंकड़े काफी अच्छे रहे हैं। सीमा शुल्क विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में चीन का निर्यात 9.9 प्रतिशत बढ़कर 239.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगस्त में निर्यात में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। इसी तरह सितंबर में आयात 13.2 प्रतिशत बढ़कर 202.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। अगस्त में चीन के आयात में 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

सितंबर में चीन का वैश्विक व्यापार 37 अरब डॉलर पर पहुंचा

कोविड-19 महामारी की वजह से दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद जल्दी खुल गई है, जिसका फायदा उसके निर्यातकों को हो रहा है। विशेषकर मास्क और चिकित्सा आपूर्ति के मामले में चीन के निर्यातकों की चांदी है और वे विदेशी प्रतिद्वंद्वियों की बाजार हिस्सेदारी भी हासिल कर रहे हैं। एक साल पहले की तुलना में सितंबर में चीन का वैश्विक व्यापार अधिशेष 6.6 प्रतिशत बढ़कर 37 अरब डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि, अगस्त के 58.9 अरब डॉलर के आंकड़े की तुलना में यह काफी कम है।

कोविड-19 के पूर्व के वृद्धि के स्तर पर चीन की अर्थव्यवस्था

चीन का अमेरिका के साथ लंबे समय से व्यापार विवाद चल रहा है। इसके बावजूद सितंबर में अमेरिका को चीन का निर्यात 20.5 प्रतिशत बढ़कर 44 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी वस्तुओं का आयात 24.5 प्रतिशत बढ़कर 13.2 अरब डॉलर रहा। चीन दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कोविड-19 के पूर्व के वृद्धि के स्तर पर पहुंची है। दूसरी तिमाही में चीन की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही है।

टोटल के सीईओ ने गौतम अडाणी के साथ परियोजाओं की समीक्षा की

नयी दिल्ली,

फ्रांस की तेल एवं गैस कंपनी टोटल एसए के सीईओ पैट्रिक पोयूयान्नी ने एक दिन की भारत यात्रा के दौरान अपनी कंपनी की अडाणी समूह के साथ संयुक्त उद्यम के तहत गैस एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा की। वह सोमवार को एक दिन के लिये अहमदाबाद पहुंचे और अडाणी समूह के साथ संयुक्त उद्यमों की समीक्षा की। अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने बैठक के बाद ट्विटर पर लिखा है, ''मेरे दोस्त, व्यापार भागीदारी और टोटल के सीईओ पी पोयूयान्नी की मेजबानी कर हमेशा खुशी होती है...हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कंपनी साहसिक कदम उठाने और बदलाव लाने के मामले में अगुवा है।'' हालांकि उन्होंने बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन सूत्रों ने कहा कि पोयूयान्नी की यात्रा शुद्ध रूप से व्यापार समीक्षा के लिये थी। उसके बाद वह तुरंत रवाना हो गये। टोटल की अडाणी की कंपनियों के साथ सिटी गैस वितरण, एनएनजी आयात टर्मिनल और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त उद्यम है। इस साल फरवरी में टोटल और अडाणी ग्रीन एनर्जी लि. (एजीईएल) ने संयुक्त उद्यम का गठन किया है। इसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50 के अनुपात में है। एजीईएल ने अपनी सौर संपत्ति संयुक्त उद्यम में हस्तांतरित की। संयुक्त उद्यम के पास 11 से अधिक भारतीय राज्यों में कुल 2,000 मेगावाट से अधिक क्षमता की हरित ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

रिलायंस जियो की एक और उपलब्धि, 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टेलिकॉम कंपनी बनी

नई दिल्लीः

रिलायंस जियो देश में 40 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली दूरसंचार सेवा कंपनी बन गई है। दूर संचार विनियामक ट्राई की सोमवार को जारी एक रपट के अनुसार कंपनी ने जुलाई में शुद्ध रूप से 35 लाख नए ग्राहक जोड़े। रपट के मुताबिक कुल देश में कुल दूरसंचार ग्राहकों की संख्या जुलाई थोड़ी बढ कर 116.4 करोड़ हो गई। जुलाई में यह संख्या 116 करोड़ थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ताजा रपट के अनुसार जुलाई में मोबाइल फोन कनेक्शन बढ़ कर 114.4 करोड़ हो गए। जून में यह संख्या 114 करोड़ थी। इनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शन क्रमशः 61.9 करोड़ और 52.1 करोड़ थे। स्थिर लाइन कनेक्शन की संख्या कई वर्ष बाद जुलाई में हल्की बढ कर 1,98,20,419 हो गई। इसमें जियो और अन्य निजी कंपनियों का बड़ा योगदान रहा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र की भारत संचार निगम लि. और एमटीएनएल तथा रिलायंस कम्यूनिकेशन्स तथा टाटा टेली सविसेज के स्थिर लाइन कनेक्शनों की संख्या में गिरावट का सिलसिला बना रहा। भारत के मोबाइल बाजार में रिलायंस जियो का हिस्सा 40,08,03,819 ग्राहकों के साथ 35.03 प्रतिशत पर पहुंच गया है। भारती एयरटेल ने जुलाई में 32.6 बीएसएनएल ने 3.88 लाख मोबाइल ग्रहक जोड़े। इसी दौरान वोडाफोन ने 37 लाख से अधिक और एमटीएनएल ने 5,457 लाख मोबाइल ग्राहक गंवाए। आलोच्य माह में ब्राडबैंड कनेक्शन की संख्या 1.03 प्रतिशत बढ़ कर 70.54 करोड़ हो गयी। जून में यह 69.82 करोड़ थी।

रुपया सात पैसे की हानि के साथ 73.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ

मुंबईः डॉलर के मजबूत होने और घरेलू शेयरों में सुस्ती के बीच मंगलवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए की विनिमय दर सात पैसे की गिरावट के साथ 73.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 73.41 पर कमजोर खुला और कारोबार के अंत में सात पैसे की गिरावट के साथ 73.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सोमवार को बंद भाव 73.28 रुपए प्रति डॉलर था। कारोबार के दौरान विनिमय दर में 73.32-73.41 के दायरे में घट बढ हुई। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के समक्ष डॉलर की घट-बढ़ दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.18 प्रतिशत मजबूत होकर 93.23 हो गया। बाजार के कारोबारी सूत्रों ने कहा कि कमजोर वृहद घरेलू आर्थिक आंकड़ों के सामने आने के बाद निवेशकों ने सतर्कता का रुख अख्तियार कर रखा है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है कि खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों की वजह से सितंबर के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति, आठ माह के उच्चतम स्तर 7.34 प्रतिशत पर जा पहुंची जो रिजर्व बैंक के लिए चिंताजनक है। अगस्त के महीने में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट जारी रही।

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, राजधानी शताब्दी सहित 40 ट्रेनें चलाएगा रेलवे

नई दिल्ली।

रेल यात्रियों को अच्छी खबर देते हुए भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जिसके चलते उत्तर रेलवे ने राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस और दूरंतो समेत और 40 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि हजरत निजामुद्दीन-पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल, नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस स्पेशल और श्री माता वेष्णों देवी कटरा-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस स्पेशल को 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा।

सेवाएं 17 अक्टूबर से शुरू

खबरों के अनुसार, उत्तर रेलवे 6 अक्टूबर से बांद्रा टर्मिनस-हजरत निजामुद्दीन युवा एक्सप्रेस स्पेशल और 17 अक्टूबर से हजरत निजामुद्दीन-बांद्रा टर्मिनस युवा एक्सप्रेस स्पेशल की सेवाएं भी शुरू करने जा रहा है। उत्तर रेलवे 15 अक्टूबर से लोकमान्य तिलक-हरिद्वार ए.सी. एक्सप्रेस स्पेशल, 17 अक्टूबर से लोकमान्य तिलक-लखनऊ ए.सी. एक्सप्रेस स्पेशल, 17 अक्टूबर से नागपुर-अमृतसर ए.सी. एक्सप्रेस स्पेशल और 12 अक्टूबर से डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी स्पेशल का परिचालन भी शुरू करेगा।

रेलवे ट्रैक पर दौड़ेंगी 120 ट्रेनें

बता दें कि रेलवे ने 25 मार्च से कोविड-19 के दौरान लागू हुए लॉकडाउन पर सभी पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद एक मई से प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया गया और 12 मई से विशेष वातानुकूलित ट्रेनों के 15 जोड़ों का परिचालन भी शुरू किया। इसके बाद एक जून को 100 जोड़ी ट्रेनों की सेवा शुरू हुई। एक सितंबर से 80 और ट्रेनों के 40 जोड़े जोड़े चालू हुए। रेलवे फिलहाल कोविड-19 महामारी के समय सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक देशभर में लिमिटेड संख्या में ट्रेन चला रहा है

कोरोना संकट से रियल एस्टेट सेक्टर को झटका, सेल में आई भारी गिरावट

नोएडा:

रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही संकट के दौर से गुजर रहा था और अब कोरोना वायरस ने रही सही कसर पूरी कर दी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट **Anarock** की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले नौ महीनों में कोविड-19 महामारी ने इस सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले साल के पहले 9 महीनों की तुलना में इस साल पूरे देश में रियल एस्टेट की बिक्री में 43 फीसदी कमी आई है।

देश के सात टॉप शहरों बेंगलूरु, एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में पिछले नौ महीनों में 88,730 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी। पिछले साल यह आंकड़ा 1,54,320 करोड़ रुपए था। इस तरह इस बार इसमें 65,590 करोड़ रुपए की कमी आई है। एनसीआर में इस दौरान कुल बिक्री 9,430 करोड़ रुपए रही जबकि पिछले साल 24,860 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। इस तरह इसमें 62 फीसदी की कमी आई थी।

NCR के शहरों का हाल

गुडगांव में इस साल अब तक केवल 3,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है जबकि पिछले साल इस दौरान 10,136 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी थी। एनसीआर के शहरों में गुड़गांव में ही सबसे अधिक बिक्री प्रभावित हुई है। नोएडा में साल के पहले नौ महीनों में प्रॉपर्टी की बिक्री 1519 करोड़ रुपए रही जबकि पिछले साल यह 3899 करोड़ रुपए रही थी। ग्रेटर नोएडा में पिछले साल पहले नौ महीनों के दौरान प्रॉपर्टी की बिक्री 5723 करोड़ रुपए रही थी जबकि इस बार यह केवल 2066 करोड़ रुपए पर आ गई। गाजियाबाद में पिछले साल सितंबर तक बिक्री 2845 करोड़ रुपए रही थी जबकि इस बार यह घटकर 1055 करोड़ रुपए पर आ गई। दिल्ली में भी प्रॉपर्टी की बिक्री 1364 करोड़ रुपए से घटकर 655 करोड़ रुपए रह गई।

अनिल अंबानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और SBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरकॉम के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी की एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय स्टेट बैंक से सोमवार को जवाब मांगा जिसमें उन्होंने उनकी दो कंपनियों के खिलाफ 1,200 करोड़ रुपए ऋण की वसूली के लिए चल रही दिवाला प्रक्रिया में चीन के कुछ लेनदार बैंकों को भी शमिल करने का अनुरोध किया है। चीनी बैंकों ने ब्रिटेन की एक अदालत से अंबानी के खिलाफ 71.7 करोड़ डॉलर की वसूली का आदेश हासिल किया है। इसी के साथ अदालत ने अंबानी की परिसंपत्ति को बेचकर वसूल करने पर लगाई रोक को भी फिलहाल जारी रखा है। अंबानी को यह छूट दिवाला एवं ऋण शोधन संहिता की धारा 96 के तहत दी गई है। अदालत की ओर से यह निर्देश अंबानी की संपत्ति बेचने को लेकर एसबीआई की स्पष्टीकरण की मांग पर दिया गया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की पीठ ने भारतीय दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) को भी अंबानी के आवेदन पर नोटिस जारी किया है। अंबानी ने मामले में चीनी बैंकों को भी पक्षकार बनाने की याचिका दायर की है ताकि वह ब्रिटेन की अदालत के मई के आदेश का पालन करने के चलते अदालत की अवमानना के मामले में ना घिर जाएं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंबानी पर उनकी परिसंपत्ति के हस्तांतरण, अलग होने, रेहन पर रखने या फिर उसके कानूनी अधिकार या हित खत्म करने पर रोक लगा दी है। यह रोक उनके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया लंबित रहने तक जारी रहेगी। अंबानी ने आरकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के लिए अगस्त 2016 में क्रमशः 565 करोड़ रुपए और 635 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एसबीआई को निजी गारंटी दी थी।

सूचीबद्धता समाप्त करने का प्रयास असफल, वेदांता ने कहा- भारत को लेकर प्रतिबद्ध

नई दिल्ली।

वेदांता लिमिटेड को भारत में शेयर बाजार से निकालने के असफल प्रयास के बाद खनन क्षत्र के प्रमुख उद्योगपति अनिल अग्रवाल की वेदांता रिसोर्सिसिज ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक भारत में वृद्धि की बेजोड़ संभावनायें उपलब्ध हैं। वेदांता लिमिटेड ने पिछले सप्ताह अपने शेयरों की भारतीय शेयर बाजारों से सूचीबद्धता समाप्त करने की पहल की थी। उसका प्रयास सफल होते होते रह गया। बोली में सार्वजनिक शेयरधाकों की ओर से शेयर वापस बेचे के बहुत से प्रस्तावों की पुष्टि नहीं होने से शेयर प्राप्त करने लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। बंबई शेयर बाजार (बीएसई) ने पुनखरीद के प्रस्ताव पर 9 अक्टूबर को सार्वजनिक शेयरधारकों के पास पड़े कुल 169.73 करोड़ शेयरों में से 137.74 करोड़ शेयरों को वापस बेचने के लिए की बोलियां पेश की गयी थीं।वैसे दिखने में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या जरूरी 134.12 करोड़ शेयर से अधिक थी लेकिन कुछ बोलियां अंत में कस्टोडियन से जरूरी पुष्टि नहीं मिलने के कारण लंबित रह गई। आखिर में आंकड़ों के मिलान में वापस बिक्री के लिए पेश शेयरों की संख्या घटकर 125.47 करोड़ रह गई। वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सिज ने एक बयान में कहा, '134 करोड़ शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करने का काम वास्तव में एक बड़ा भारी काम है। इस काम में हमें हमारे शेयरधारकों से बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखी, हम अपने लक्ष्य से केवल सात प्रतिशत दूर रह गये।'कंपनी ने कहा सूचीबद्धता का प्रयास सफल नहीं रहा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.15 अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता। इस बड़े पैमाने के कोष का अर्थव्यवस्था में कई गुणा तक 0.4 प्रतिशत से लेकर 0.8 प्रतिशत के दायरे में असर होता। वेदांता लिमिटेड में रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया की शुरुआत 5 अक्टूबर को हुई और 9 अकटूबर को यह पूरी हुई।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

द. कोरिया से 14 नवंबर को दोस्ताना मैच खेलेगा मेक्सिको

मेक्सिको सिटी. मेक्सिको की फुटबाल टीम अगले महीने दक्षिण कोरिया के साथ एक दोस्ताना मैच खेलेगा ताकि वह 2021 गोल्ड कप और कॉकाकाफ विश्व कप क्वालीफायर्स के फाइनल राउंड के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत दी सके। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह मैच आस्ट्रिया में 14 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया के साथ अब तक 13 मैच खेले हैं, जिसमें उसने सात जीते हैं और दो ड्रॉ खेले हैं। मेक्सिको की टीम उन पांच टीमों में से एक है, जो पहले ही 2022 विश्व कप क्वालीफायर्स के अंतिम चरण के लिए प्रवेश कर चुकी है। अन्य टीमों में अमेरिका, कोस्टा रिका, जमैका और होंडुरस शामिल है। मेक्सिको ने पिछले सप्ताह ही खेले गए एक दोस्ताना मैच में नीदरलैंडस को 1-0 से हराया था और अब उसे मंगलवार को अल्जेरिया से भिड़ना है।

आईपीएल-13

राजस्थान की कोशिश दिल्ली से हिसाब बराबर करने की

दुबई।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन का दूसरा हाफ शुरू हो गया है। इसी क्रम में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर आमने-सामने होंगी और स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली राजस्थान इस मैच में पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। दोनों टीमें नौ अक्टूबर को शारजाह में भिड़ी थीं, जहां दिल्ली ने 46 रनों से मुकाबला जीता था। लेकिन उस राजस्थान और इस राजस्थान की टीम में अंतर है। वो है बेन स्टोक्स। स्टोक्स ने इस सीजन के अधिकतर मैच नहीं खेले हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछला मैच खेला था जिसमें सफल नहीं रहे थे। स्टोक्स को टीम प्रबंधन ने सलामी बल्लेबाजी करने उतारा था, लेकिन यह दिग्गज सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गया था। गेंदबाजी में भी सिर्फ एक ओवर फेंका था और सात रन दिए थे। स्टोक्स उस समय क्वारंटीन से लौटे थे और एक दिन अभ्यास के बाद ही मैदान पर उतर गए थे। इसलिए लय में आना उनके लिए मुश्किल रहा होगा। अब जबकि उन्होंने दो दिन अभ्यास कर लिया तो लय हासिल कर ली होगी और ऐसे में यह हरफनमौला खिलाड़ी हर लिहाज से दिल्ली के लिए बड़ा खतरा है। स्टोक्स इस मैच में पारी की शुरूआत करेंगे या नहीं यह देखना होगा। लेकिन राजस्थान के लिए बेहतर होगा कि वो स्टोक्स को मध्य क्रम में खेलाए क्योंकि मध्य क्रम या निचले क्रम में टीम के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो शीर्ष क्रम के विफल होने के बाद टीम को संभाल सके। वहीं संजू सैमसन का लगातार गिरता ग्राफ भी टीम के लिए चिंता है। शुरूआती मैचों में तूफानी पारियां खेलने वाले संजू शांत हो गए हैं। जोस बटलर और स्टीव स्मिथ दो और ऐसे बल्लेबाज हैं जो राजस्थान की किस्मत बदल सकते हैं। पिछले मैच में राहुल तेवतिया और रियान पराग ने हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली थी। इसलिए इन दोनों का आत्मविश्वास भी ऊपर ही होगा, लेकिन निरंतरता बनाए रखना तेवतिया के लिए भी चुनौती है और पराग के लिए भी। पंजाब के बाद मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद तेवतिया की फॉर्म में गैप आ गया था जो हैदराबाद के खिलाफ मैच में टूटा। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर को स्टोक्स का सहयोग मिलेगा तो यह इंग्लिश जोड़ी दिल्ली के मजबूत बललेबाजी क्रम को रोकने का दम रखती है। दिल्ली को इस मैच में ऋषभ पंत की कमी खल सकती है जो लगभग एक सप्ताह के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह आए एलेक्स कैरी तेजी से रन तो बना सकते हैं लेकिन पंत का अंदाज जुदा है और जिस तरह से पंत बल्लेबाजी करते हैं उनका कोई सानी नहीं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ टीम को पंत की कमी साफ खली थी और टीम उतना स्कोर नहीं बना पाई थी जितना उसे बनाना चाहिए था। हां पिछले मैच में दिल्ली के लिए अच्छी बात यह रही थी कि शिखर धवन की फॉर्म लौट आई थी। वह 69 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। पृथ्वी शॉ, कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला भी चल रहा है निचले क्रम में मार्कस स्टोयनिस टीम के लिए बड़े खिलाड़ी साबित हुए हैं।

अगरकर ने आईपीएल प्लेऑफ के लिए मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को चुना

दुबई।

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर का मानना है कि आईपीएल के 13वें संस्करण में प्लेआफ में पहुंचने वाली चार टीमों में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगी। मुंबई और दिल्ली लीग के 13वें सीजन में क्रमश = पहले और दूसरे नंबर पर है जबकि कोलकाता चौथे नंबर पर है। अगरकर ने क्रिकेट कनेक्टेड कार्यक्रम में कहा, यह काफी करीबी टूर्नामेंट है और इसमें काफी सारे उतार-चढ़ाव हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल दो सर्वश्रेष्ठ टीमों की तरह दिखते हैं। मेरे विचार से केकेआर को सीएसके के खिलाफ एक वास्तविक बोनस जीत मिली। वे मेरी तीसरी टीम हैं। अगरकर का मानना है कि प्लेआफ में पहुंचने वाली चौथी टीम राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद में से कोई एक टीम होगा। उन्होंने कहा, मेरे लिए चौथी टीम राजस्थान और हैदराबाद में से होगी। शुरूआत में मैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था, इस समय ये दोनों टीमें चेन्नई से बेहतर खेल रही है।

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स सात मैचों में दो ही जीती है और वह सातवें नंबर पर है।

सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 12 दिसंबर से बेलग्रेड में

कोरसिएर सुर वेवेय (स्विटजरलैंड)। सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 12 से 20 दिसंबर तक सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। कुश्ती की विश्व संस्था-यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने घोषणा की है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू कार्यकारी समिति की सोमवार को यहां बैठक हुई, जिसमें चैंपियनशिप को आयोजित कराने को मंजूरी दी गई। बैठक में 70 फीसदी भागीदार देशों ने इसमें अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि कार्यकारी समिति छह नवंबर को फिर से अपनी बैठक करेगी और कोरोना वायरस के कारण इस पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेगी। इस बीच, बेलग्रेड में ही होने वाली जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप को कोरोना महामारी के चलते मौजूदा हालात के कारण रद्द कर दी गई है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि बैठक में फैसला किया गया कि मौजूदा हालात चैंपियनशिप को आयोजित कराने के लिए अनुकूल नहीं हैं इसलिए जूनियर विश्व चैंपियनशिप को रद्द किया जा रहा है।

शास्त्री ने डिविलियर्स से संन्यास से वापस आने का अनुरोध किया

शारजाह।

भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान अब्राहम डिविलियर्स से संन्यास से वापस आने और फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुरोध किया है। डिविलियर्स ने सोमवार को आईपीएल-13 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मात्र 33 गेंदों पर ही 73 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में पांच चौके और छह छक्के लगाए। डिविलियर्स की आखिरी ओवरों में खेली गई शानदार पारी के दम पर बेंगलोर ने सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 195 रनों की चुनौती रखी और फिर कोलकाता को 82 रनों से करारी शिकस्त दी। शास्त्री ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा, कल रात लोगों ने जो देखा वह अदभुत था और आज उठने के बाद भी अहसास वही है। एबी डिविलियर्स इन कठिन परिस्थितियों में या फिर वैसे भी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी जरूरत है। संन्यास से वापस आइए। आपकी वापसी से यह खेल और बेहतर होगा। डिविलियर्स ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने दक्षिण अफीका के लिए 114 टेस्ट मैच, 228 वनडे और 78 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। आईपीएल के मौजूदा 13वें सीजन में वह अब तक बेंगलोर के लिए सात मैचों में अब तक 228 रन बना चुके हैं।

संक्षिप्त समाचार

पेट दर्द से उबरे क्रिस गेल ट्रेनिंग पर लौटे

शारजाह। आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल पेट दर्द (फूड प्वॉइजनिंग) से उबरकर ट्रेनिंग के लिए मैदान पर लौट आए हैं। गेल को अब गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए अंतिम एकादश में शामिल किया जा सकता है। किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने आधिकारिक टिवटर पर कहा कि गेल ट्रेनिंग के लिए वापस मैदान पर लौट आए हैं। गेल ने इस सीजन अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। उनकी टीम अंकतालिका में सबसे नीचे बनी हुई है। किंग्स इलेवन पंजाब के सहायक कोच वसीम जाफर ने कहा, क्रिस गेल तैयार दिख रहे हैं और वह मैदान में जाने के लिए उत्सुक है। वह वास्तव में अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले रहे हैं और नेटस पर वास्तव में अच्छा लग रहे हैं। गेल आठ अक्टूबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पेट खराब होने के कारण मैच नहीं खेल पाए थे। टीम के कोच अनिल कुंबले ने कहा था, गेल आज का मैच खेलने वाले थे लेकिन वो बीमार हैं। उन्हें फूड पोइजनिंग हुई है इसलिए वो अंतिम-11 में नहीं हैं। पंजाब को बल्लेबाजी में समस्या हो रही है। उसके कप्तान लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल को छोड़कर कोई और बल्लेबाज रन नहीं कर पा रहा है।

ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही समय पर शिखर पर पहुंचना होगा - गुरजीत

नई दिल्ली।

भारतीय महिला हॉकी टीम की ड्रैगफ्लिकर गुरजीत कौर का मानना है कि टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के दौरान खिलाड़ियों को उन सभी सही चीजों को याद रखना होगा जो उन्होंने हाल में शीर्ष टीमों के खिलाफ की थीं। 25 साल की गुरजीत ने कहा, पिछले साल शीर्ष टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रतिस्पर्धा करने और एफआईएच सीरीज फाइनल्स जैसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के बाद हमारी टीम के खिलाड़ियों ने खुद पर ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हम शीर्ष टीमों के खिलाफ और आने वाले महीनों में अपने खेल को बनाने वाली सभी सही चीजों को याद रखें। हमें ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही समय पर शिखर पर पहुंचना है। भारत के लिए अब तक 80 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकीं गुरजीत ने आगे कहा कि कोविड-19 के रूकाव के बाद 19 अगस्त से फिर से खेल गतिविधियों के शुरू होने के बाद प्रत्येक सत्र के साथ खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। गुरजीत ने कहा, पिच पर वापसी करना निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। हालांकि, हमें अभी भी बहुत अधिक कुछ नहीं देने के बारे में सावधान रहना होगा। सभी खिलाड़ी खेल गतिविधियों के हर सत्र के साथ आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा, हम सभी के लिए यह कठिन समय है और इसलिए हम हॉकी इंडिया के प्रति बहुत आभारी हैं। इस दौरान हमें जो कुछ भी चाहिए, उसकी शानदार सुविधाओं के लिए, हॉकी इंडिया और साई ने हमारी शानदार मदद की है।

बैडमिंटन : लक्ष्य सेन डेनमार्क ओपन के दूसरे दौर में

ओडेंसे (डेनमार्क)। भारत के लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन कोर्ट पर विजयी वापसी करते हुए यहां जारी डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बना ली है। लक्ष्य ने मंगलवार को पुरुष एकल के पहले दौर में वर्ल्ड नंबर-77 फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को सीधे गेमों में 21-9, 21-15 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वर्ल्ड नंबर-27 भारतीय खिलाड़ी ने 36 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम किया। दूसरे दौर में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के विटिंगस से हो सकता है। इस बीच, तीन साल पहले यहां खिताब जीतने वाले पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 किदांबी श्रीकांत वर्ल्ड नंबर-52 इंग्लैंड के टॉबी पेंटी के खिलाफ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरूआत करेंगे।वहीं, अजय जयराम स्थानीय खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर-3 एंडर्स एंटनसन से जबकि शुभंकर डे कनाडा के जेसन एंथनी के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान की शुरूआत करेंगे। महिला वर्ग में भारत की ओर से एक भी चुनौती नहीं है क्योंकि सायना नेहवाल और पीवी सिंधु पहले ही टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुकी है। यह सुपर 750 टूर्नामेंट 18 अक्टूबर तक डेनमार्क के में खेला जाना है, जोकि कोविड-19 महामारी के कारण आई रूकावट के बाद अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर को फिर से शुरू हुआ है। विश्व बैडमिंटन संघ (बीडब्ल्यूएफ) ने इससे पहले ने थॉमस और उबर कप फाइनल्स के अलावा डेनमार्क मास्टर्स को भी रद्द कर दिया था।

डिफेंडर स्कॉट नेविले लोन पर ईस्ट बंगाल से जुड़े

कोलकाता। ईस्ट बंगाल ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी सातवें सीजन से पहले मंगलवार को ए-लीग के अनुभवी डिफेंडर स्कॉट नेविले को लोन पर एक सीजन के लिए अपने साथ जोड़ने की घोषणा की है। नेविले ए-लीग में ब्रिस्बेन रोर का हिस्सा थे। 31 साल के नेविले ने 2019-20 सीजन में ब्रिस्बेन रोर की ओर से दो मैचों को छोड़कर सभी मैचों में खेले थे। उन्होंने ब्रिस्बेन की टीम को ए-लीग में चौथे स्थान पर जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेविले ने ब्रिस्बेन में अपने पदार्पण सीजन में 25 मैच खेले थे। नेविले ने कहा, भारत मेरे लिए एक नई चुनौती पेश करता है और मैं ईस्ट बंगाल की जर्सी पहनने और मैदान में उतरने का और इंतजार नहीं कर सकता। हमेशा हमसे बड़े पैमाने पर उम्मीदें रहेंगी और मुझे इसकी जानकारी है। मैं ब्रिसबेन रोर फुटबॉल क्लब को भी इस कदम को संभव बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

टेनिसः चोट के कारण सेंट पीटर्सबर्ग ओपन से हटे सितसिपास

नई दिल्ली। वर्ल्ड नंबर-5 ग्रीस के स्टेफानो सितसिपास चोट के कारण सोमवार से शुरू हुए सेंट पीटर्सबर्ग ओपन से हट गए हैं। सितसितपास ने टिवटर पर इसकी जानकारी दी। सितसिपास ने बताया कि टांग की चोट के कारण ही उन्होंने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। सितसिपास को यह चोट फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में लगी थी, जहां उन्हें पांच सेटों तक चले कड़े मुकाबले में 17 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सार्बिया के नोवाक जोकोविच से हार का सामना करना पड़ा था। सितसिपास ने कहा, दोस्तों मैं अपने दुनियाभर के तमाम फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले सप्ताह से रोलां गैरो में मेरा समर्थन किया। पेरिस में मेरा समय बहुत ही अच्छा था और मैंने जोकोविच के खिलाफ सेमीफाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश, मेरी टांगों में चोट लग गई थी, लेकिन मैंने एमआरआई करवाया और इसकी टेस्ट करवाई। डॉक्टर की सलाह के बाद मैंने सेंट पीटसबर्ग से हटने का फैसला किया है। विंयना की तैयारियों के लिए मैं एक सप्ताह का आराम लेना चाहता हूं। मैं वहां खेलने को लेकर उत्साहित हूं। पेरिस और लंदन के लिए क्वालीफाई करने के बाद मेरे पास अपना खिताब बचाने का मौका है।

दिल्ली कैपिटल्स को लगा दूसरा बड़ा झटका, अमित मिश्रा के बाद अब ईशांत शर्मा चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर

डिजिटल डेस्क।

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) को दूसरा झटका लगा है। दिल्ली के अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के कारण IPL से बाहर हो गए हैं। इससे पहले अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा चोट के कारण बाहर हो चुके है। दिल्ली कैपिटल्स ने एक बयान में कहा कि, ईशांत को सात अक्टूबर को ट्रेनिंग सेशन के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। 32 वर्षीय ईशांत इस सीजन में सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही मैच खेल पाए थे, जिसमें उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को सात अक्टूबर को दुबई में टीम प्रशिक्षण सत्र में गेंदबाजी करते समय बाएं पसली में दर्द महसूस हुआ था। इसके बाद जांच में पता चला कि उनके बाएं मांसपेशियों में खिंचाव है। यह चोट दुर्भाग्य से उन्हें IPL-13 से बाकी बचे मैचों से बाहर कर देगी। इशांत और मिश्रा के अलावा दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण अगले एक हफ्ते तक के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।

पंत चोट के कारण अगले एक हफ्ते तक टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे

बता दें कि, पंत चोट के कारण अगले एक हफ्ते तक टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। वह चोट के चलते रविवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मैच में भी नहीं खेले थे। पंत को शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। पंत को डॉक्टरों ने एक हफ्ते आराम करने के लिए कहा है। मुंबई के खिलाफ हुए मैच में दिल्ली को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। मैच में दिल्ली ने मुंबई को 163 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में मुंबई ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाकर मैच जीता। दिल्ली के कप्तान अय्यर ने मुंबई के खिलाफ मैच के बाद पंत की इंजरी पर कहा था कि, डॉक्टरों ने पंत को एक हफ्ते आराम करने की सलाह दी है। मुझे उम्मीद है कि ब्रेक के बाद वह जोरदार वापसी करेंगे। पंत ने इस सीजन में दिल्ली के लिए अब तक 6 मैचों में 35.70 की औसत से 176 रन बनाए हैं।

चहल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था : स्टोक्स

शारजाह। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और इसलिए उस मैच में चहल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलना चाहिए था। आईपीएल-13 में सोमवार को शारजाह में हुए मुकाबले में बेंगलोर की टीम ने कोलकाता को 82 रन से करारी शिकस्त दी। चहल ने चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक का विकेट लिया। स्टोक्स ने मैच के बाद ट्वीट किया, बल्लेबाजों के इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था। शानदार गेंदबाजी आक्रमण खास तौर पर जब यह मैच शारजाह में खेला गया हो। बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 194 का स्कोर बनाया था। अब्राहम डीविलियर्स ने 33 गेंद पर 73 रन की पारी खेली थी। अपनी पारी में उन्होंने पांच चौके और छह छक्के लगाए और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। चहल ने इस सीजन में अब तक 10 विकेट लिए हैं। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलोर की टीम सात मैचों में पांच जीत के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बिहार फिर शर्मसार! दानापुर में मदद के बहाने बिहिया की नाबालिग से 4 युवकों ने किया गैंगरेप

पटना। बिहार फिर शर्मसार। आशियाना से दानापुर जंक्शन ट्रेन पकड़कर अपने घर बिहिया जाने के लिए निकली नाबालिग लड़की शनिवार की रात रास्ते में दरिंदगी की शिकार हो गई। ऑटो में बैठने के बाद चालक की नीयत खराब हो गई। ट्रेन नहीं होने व रात होने की बात कहकर ऑटो चालक ने नाबालिग लड़की को बहलाया-फुसलाया। बाद में उसे दानापुर थाना क्षेत्र के लेखानगर स्थित एक गोदाम में ले गया। जहां ऑटो चालक ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ नाबालिग से गैंगरेप किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली। केस दर्ज कर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों राजेश, तुलसी और कल्लू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार ऑटो चालक टमाटर उर्फ करमू की तलाश की जा रही है।

ऑटो में पहले से सवार था एक, दो को फोन कर बुलाया

पीड़िता की उम्र करीब 14 वर्ष है। उसके मुताबिक, वह आशियाना में एक महिला के यहां दाई का काम करती थी। शनिवार की रात किसी बात को लेकर मकान मालकिन से उसका झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर वह अपने घर बिहिया जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ी। सगुना मोड़ पहुंचने के बाद दानापुर स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो पकड़ा। ऑटो में चालक टमाटर उर्फ करमू का साथी राजेश बैठा था। दोनों बातचीत करते हुए दानापुर स्टेशन के लिए चल पड़े। कुछ दूर जाने पर चालक ने कहा कि बिहिया जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मेरे घर चलिए और मेरे बच्चों का देखभाल कीजिएगा। पीड़िता दोनों के झांसे में आ आ गई। इसके बाद चालक उसे ऑटो से अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में ही चालक और उसके दोस्त ने अपने दो साथियों तुलसी और कल्लू को भी फोन कर दिया। बताया गया है कि लेखा नगर निवासी सुबोध सिंह के मकान में कल्लू ने एक गोदाम किराये पर ले रखा है।

अभी और एक महीना नहीं खुलेगा स्कूल, जानें क्यों हिचक रहे हैं राज्य

नयी दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण देशभर में स्कूल, कॉलेज-विश्वविद्यालय 16 मार्च से ही बंद चल रहे हैं. अब केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से इन्हें क्रमिक तरीके से पुन- खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लगभग सभी राज्य इस महीने स्कूल खोलने के मूड में नहीं दिख रहे. पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य तो दीपावली के बाद ही इस बारे में सोचना चाहते हैं. दीपावली इस साल 14 नवंबर को पड़ रही है. केंद्र की ओर से जारी दिशानिर्देशों में शिक्षण संस्थानों को पुन- खोलने का अंतिम निर्णय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर छोड़ा गया है. कुछ राज्यों ने नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को सीमित स्तर पर खोला है या खोलने की तैयारी है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 31 अक्तूबर तक बंद ही रखने का फैसला किया है. इसके बाद हालात की समीक्षा की जायेगी. कर्नाटक सरकार ने कहा है कि उसे स्कूलों को पुन- खोलने की कोई हड़बड़ी नहीं है और वह सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद इस बारे में निर्णय लेगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि राज्य के स्कूल महामारी के मद्देनजर अगले आदेश तक बंद रहेंगे. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि दीपावली के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का आकलन कर कोई फैसला लेंगे. गुजरात सरकार का भी ऐसा ही मत है. राज्य शिक्षा विभाग के सचिव विनोद राव ने कहा कि दीपावली की छुट्टियां बीतने के बाद कोरोना संक्रमण संबंधी हालात का आकलन कर स्कूल फिर से खोलने पर विचार करेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला मध्य नवंबर के बाद ही लिया जायेगा. हरियाणा सरकार छठी से नौवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही है, ताकि वे शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर

सकें, लेकिन इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. आंध्र प्रदेश सरकार ने भी दो नवंबर तक सामान्य तरीके से कक्षाएं बहाल नहीं करने का फैसला किया है. मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल फिलहाल नहीं खुलेंगे. राज्य में 21 सितंबर से सीमित छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं के लिए स्कूलों को खोला गया है. बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य दीपावली बाद ही करेंगे विचार.

उत्तर प्रदेश- बड़े बच्चों के लिए 19 से खुल सकेंगे स्कूल- लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 19 अक्तूबर से पुन- खोले जा सकेंगे. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शारीरिक दूरी के पालन के लिए कक्षाएं पालियों में होंगी. छात्रों को अपने अभिभावकों की लिखित अनुमति जमा करनी होगी.

कर्नाटक-30 तक छुट्टी, ऑनलाइन क्लास भी नहीं होंगी- बेंगलुरु. कर्नाटक में कई शिक्षकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरों के मद्देनजर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को राज्य में सभी प्रकार की स्कूली गतिविधियों के लिए 12 से 30 अक्टूबर तक छुट्टी का आदेश दिया है. इस दौरान ऑनलाइन शिक्षा का 'विद्यागमा कार्यक्रम' भी बंद रहेगा.

ठंड और त्योहारों के दौरान बढ़ सकता है संक्रमण, भीड़ से दूरे रहें लोग- हर्षवर्धन -केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को आगाह किया कि ठंड के मौसम और त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है. ऐसे में यदि लोग त्योहार मनाने के लिए भीड़ एकत्र करते हैं, तो हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. उन्होंने लोगों से भीड़ से दूर रहने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि मेला और पंडालों में जाने के बजाय घर में ही अपने प्रियजनों के साथ उत्सवों का आनंद लें.

वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर फैसला नहीं, जल्द शुरू हो सकती है 'फेलूदा जांच'- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया है. इसकी अनुमति देने के लिए सुरक्षा और प्रभाव संबंधी पर्याप्त आंकड़ों की जरूरत होगी. इसके आधार पर ही कोई फैसला लिया जा सकगा. कहा कि कोरोना का पता लगाने के लिए 'फेलूदा पेपर स्ट्रिप' जांच अगले कुछ हफ्ते में शुरू की जा सकती है.

मनरेगा के लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रही केंद्र सरकार, ग्रामीणों को रोजगार देने के प्रयास

नई दिल्ली। भारत के चालू वित्त वर्ष की हालात सबसे ज्यादा मंदी के दौर में है। इसी के चलते केंद्र ने अपने प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किया है। जिसमें हर पांच भारतीयों में से एक का नामांकन किया गया है। इसका लक्ष्य है 320 करोड़ दिनों का काम प्रदान करना ये पहले के मुकाबले 40 करोड़ अधिक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है जिसे कोरोना महामारी के बीच लोगों के लिए पेश किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश समेत घनी आबादी वाले 8 राज्यों ने केंद्र से मनरेगा के तहत नई वर्क लोकेशन के लिए अनुरोध किया है। कई अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया है कि बढ़ती बेरोजगारी और मजदूरी में कटौती के कारण आने वाले महीनों में देश को मांग को झटका लग सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को भविष्यवाणी की कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 9.5त्न की कमी झेल सकती है जो देश की सबसे खराब मंदी है।

मई में सरकार ने अपने प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में 1 लाख करोड़ तक की बढ़ोतरी के लिए मनरेगा के बजट को बढ़ाने के लिए अलावा 40,000 करोड़ का भुगतान किया। इसने पहले काम के 281 करोड़ दिनों के अनुमान से लेकर 300 करोड़ दिनों के रोजगार के लक्ष्य को भी उठाया। अधिकारियों ने कहा कि 221.9 करोड़ दिनों का काम पहले ही 7 अक्टूबर तक पूरा हो चुका था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंतरिक नोट बताते हैं कि मई से हर महीने श्रमिकों की औसत संख्या वित्त वर्ष 2019-20 में इसी महीने की तुलना में काफी अधिक रही है। एक नोट में कहा गया है, मई में पेश किए जाने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 2.51 करोड़ प्रति दिन है, जो पिछले साल मई में दिए गए प्रस्ताव की तुलना में 73 प्रतिशत अधिक है, जो प्रति दिन 1.45 करोड़ व्यक्ति था। इसी तरह, जून में प्रति दिन औसतन 3.35 करोड़ लोगों को काम की पेशकश की गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 92त्न अधिक है। ÷ नोट में बताया गया कि जुलाई औसत 114त्न अधिक था, अगस्त (97त्न), सितंबर (86त्न) और अक्टूबर औसत पिछले वर्ष की तुलना में 109त्न अधिक था।

कांग्रेस के लिए अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती, इस बार मांगने होंगे JDU के खिलाफ वोट, कम हो सकता है स्ट्राइक रेट

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के सामने अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। पार्टी इस बार पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है, पर गठबंधन का स्वरुप बदल गया है। पार्टी को इस बार उसी जेडीयू के खिलाफ वोट मांगने होंगे, जिसके साथ गठबंधन में उसने 2015 के चुनाव में पिछले दो दशक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

कांग्रेस इस बार वर्ष 2015 के मुकाबले काफी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीट पर चुनाव लड़कर 27 सीट दर्ज की थी। जबकि इस बार पार्टी 70 सीट पर किस्मत आजमा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि वह अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने में सफल रहेगी, पर कई नेता मानते हैं कि

कांग्रेस इस बार वर्ष 2015 के मुकाबले काफी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 41 सीट पर चुनाव लड़कर 27 सीट दर्ज की थी। जबकि इस बार पार्टी 70 सीट पर किस्मत आजमा रही है। पार्टी को उम्मीद है कि वह अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने में सफल रहेगी,

पार्टी की स्ट्राइक रेट कम हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीस से अधिक सीट हासिल करने के लिए कांग्रेस को पूरे 15 साल इंतजार करना पड़ा है। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 23 सीट मिली थी। पर वर्ष 2005 में हुए चुनाव में पार्टी सिर्फ 10 सीट ही हासिल कर पाई। इसके बाद 2010 के चुनाव में कांग्रेस के चार उम्मीदवार ही जीत पाए। जबकि कांग्रेस सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि बिहार की मौजूदा राजनीतिक हालात में पार्टी के अपना पिछले प्रदर्शन दोहराना यकीकन एक चुनौती है। क्योंकि, गठबंधन बदल गए हैं। वर्ष 2015 में कांग्रेस, राजद और जेडीयू का वोट एकजुट था, इस बार जेडीयू भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है। जाहिर है, चुनाव पर इसका असर होगा पर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है।

पार्टी का मानना है कि चुनाव में 27 सीट जीतने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े हैं। यह उम्मीद जगी है कि बिहार में कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधार सकती है। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। खासकर कोरोना में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर उन पर सवाल उठे हैं। ऐसे में राजद-कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा।

लीबिया में 14 सिंतवर को अगवा किए गए थे बिहार सहित 4 राज्यों के 7 भारतीय

मोदी सरकार के एक्शन से सभी सुरक्षित रिहा

नई दिल्ली। लीबिया में अगवा किए गए सात भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। ट्यूनिशिया में भारत के राजदूत ने रविवार को यह जानकारी दी। आपको बता दें कि जिन सात भारतीयों की बीते 14 सितंबर को लीबिया के अश्शरीफ अपहरण किया गया था वे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों के रहने वाले हैं। ट्यूनिशिया में भारतीय दूत पुनीत रॉय कुंडल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को उनकी रिहाई की खबर की पुष्टि की। आपको बता दें कि लीबिया में भारत दूतावास नहीं है। ट्यूनिशिया स्थित भारतीय मिशन ही लीबिया में भारतीयों के के लिए काम करता है। गुरुवार को भारत ने पुष्टि की थी कि पिछले महीने लीबिया में उसके सात नागरिकों का अपहरण कर लिया गया था और उनकी रिहाई के लिए हर संभव प्रया स किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि अपहृत श्रमिक सुरक्षित हैं और ट्यूनिशिया में भारतीय मिशन उन्हें मुक्त करने के प्रयासों के लिए लीबिया सरकार के संपर्क में है।

MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, ट्यूनिशिया में हमारा दूतावास, जो लीबिया में भारतीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित मामलों को संभालता है, लीबिया के सरकारी अधिकारियों तक पहुंच गया है। वहां मौजूद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भारतीय नागरिकों को बचाने में उनकी मदद लेने के लिए नियोक्ता को नियुक्त किया है।÷ उन्होंने यह भी कहा था कि अपहरणकर्ताओं द्वारा संपर्क किया गया और सबूत के तौर पर दिखाया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अच्छी तरह से रख रहे हैं। सितंबर 2015 में भारतीय नागरिकों को वहां की सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लीबिया की यात्रा से बचने के लिए एक सलाह जारी की गई थी।

सुशांत सिंह राजपूत केस-रिया चक्रवर्ती के वकील बोले-उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं

नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती को रिहा हुए चार दिन हो गए हैं और अब उनके वकील का एक बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के वकील, एडवोकेट सतीश मानेशिंदे ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा मैंने कहा था कि एक बार जब रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर हो जाती है, तो हम उन लोगों के पीछे जाना शुरू कर देंगे। जिन्होंने उन्हें बदनाम किया और उनके मनोबल

को गिराने की कोशिश वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फेक न्यूज चलाकर दो मिनट की ग्लोरी के लिए।

हम केंद्रीय जांच ब्यूरो को उन लोगों की एक सूची को आगे बढ़ाएंगे, जिन्होंने टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फर्जी और झूठे दावे किए। जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मामले पर मोबाइल रिकॉर्डिंग और फर्जी खबरों को शामिल किया गया। विशेष रूप से रिया चक्रवर्ती के संदर्भ में। हम सीबीआई से जांच को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध करेंगे।

रिया के वकील का संदर्भ विशेष रूप से रिया की पड़ोसी डिंपल थवानी के लिए था जिन्होंने ये बयान दिया कि किसी ने उन्हें बताया कि सुशांत सिंह 13 जून को रिया को घर छोड़ दिया था। मनशिंदे ने कहा की सीबीआई ने उनका बयान रविवार को दर्ज किया था। रिया चक्रवर्ती को पिछले महीने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वे सुशांत को नशीली दवाओं का सेवन कराती थी। 7 अक्टूबर को उन्हें रिहा कर दिया गया था। राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया था कि चक्रवर्ती ने राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपये इधर-उधर किए हैं।रिया पर ये भी आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सुशांत को दूसरों से अलग किया था और सुशांत के क्रेडिट कार्ट भी उनके ही पास थे।

पूर्व वनमंत्री उमंग सिंघार कोरोना पॉजिटिव, देशवासियों से की ये अपील

पूर्व वनमंत्री उमंग सिंघार को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे. इसके अलावा उन्होंने लोगों से बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को जितवाने की अपील की.

ोपाल. कांग्रेस नेता और पूर्व वनमंत्री उमंग सिंघार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इस बात की जानकारी उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर दी. पूर्व मंत्री ने कहा कि उनकी रिपोर्ट जांच में कोरोना पॉजिटिव आई है. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में आपका साथ और स्नेह मेरी सबसे बड़ी ताक़त है! जल्द स्वस्थ होकर आपके बीच आऊंगा. साथ ही उन्होंने लोगों से खुद का और प्रियजनों का ध्यान रखने की अपील की.

र्व वनमंत्री उमंग सिंघार को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. उन्होंने कहा कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर लौटेंगे. इसके अलावा उन्होंने बदनावर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल को जितवाने की बात कही.

ापको बता दें कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा बड़े नेता और मंत्री संक्रमित हो चुके है. प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ कैबिनेट के 7 मंत्री तक करोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं. इनमें गोपाल भार्गव, अरविंद सिंह भदौरिया, प्रभु राम चौधरी, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट, मोहन यादव और रामखेलावन पटेल शामिल

मंत्री मोहन यादव का विवादित बयान, 'हम BJP के लोग हैं बुरा करने वालों को जमीन में दफना देंगे'

संबोधन के दौरान उन्होंने आगर मालवा बिधानसभा सीट के कांग्रेस प्रभारी जयवर्धन सिंह पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि नगली राजा के छोरे को लेकर आए, हम सबको ठिकाने लगा देंगे.

आगर-मालवा. मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में प्रचार करने के लिए पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बेतुका बयान दे डाला. एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक इसलिए नहीं होते हैं कि सरपंचों का शिकार करें. शिकार करना है और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जंगल में जाओं और जानवर मारो.

इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस सरकार में अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए धर्मशाला को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में तुम हमारे समुदाय का धर्मशाला तोड़ने पहुंच गए थे. तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ?उज्जैन लंका में नहीं है, हम दौड़े चले आएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे. उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई अगर बुरा करेगा तो हम उसे घर से निकाल लाएंगे और जमीन में गाड़ (दफना) देंगे.

संबोधन के दौरान उन्होंने आगर मालवा बिधानसभा सीट के कांग्रेस प्रभारी जयवर्धन सिंह पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि नगली राजा के छोरे को लेकर आए, हम सबको ठिकाने लगा देंगे.

वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के इस बयान की कांग्रेस प्रदेश सचिव गुड्डू लाला ने निंदा की है. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ही इस तरह के बयान देंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा. बच्चों को क्या सीख मिलेगी ? आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी ?

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं.

जिसके लिए वोटिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि रिजल्ट 10 नवंबर को जारी किया जाएगा. उपचुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी के नेता अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार के लिए जुट गए हैं.

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

44 ब्रिज खोले जाने पर भड़का चीन बोला-भारत ने गैरकानूनी तरीके से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया

नेशनल डेस्क:

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमा के नजदीक 44 नए के उद्घाटन पर चीन को तीखी मिर्ची लगी है। चीन ने 44 नए ब्रिज खोले जाने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने गैरकानूनी तरीके से लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाया। चीन ने कहा कि वह लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्सयता नहीं देता है। चीन ने कहा कि वह क्षेत्र में इन्सफ्रास्ट्रक्सचर निर्माण का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्सता झाओ लीजियान ने सीमा पर अधोसंरचना निर्माण को दोनों पक्षों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बताते हुए कहा कि किसी भी पक्ष में ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि तनाव में इजाफा हो। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सामीवर्ती इलाकों में बनाए गए 44 पुलों को सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया। ऑनलाइन कार्यक्रम में पुलों का उद्घाटन करते हुए सिंह ने अपने संक्षिप्त संबोधन में पाकिस्तान और चीन से लगती भारत की सीमा पर स्थिति का हवाला दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन। ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। बता दें कि लद्दाख में पिछले लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर सोमवार को पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की वार्ता दोपहर लगभग 12 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चुशूल क्षेत्र में भारतीय इलाके में हुई और रात साढ़े आठ बजे के बाद भी जारी रही। विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखते हैं क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग एक लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं जो लंबे गतिरोध में डटे रहने की तैयारी है। सूत्रों ने कहा कि एजेंडा विवाद के सभी बिन्दुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने का था।

रूस अमेरिका को देगा कोरोना वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला!

मॉस्को:

रशियन डाइरेक्ट इंवेस्टमेंट फंड (आरडीआईएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरिल मित्रेव ने मंगलवार को सीएनएन के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक वी की सुरक्षा के बारे में अमेरिका की चिंताओं को दूर करने के लिये रूस अमेरिका के एलर्जी एवं संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक एंथनी फौसी के साथ अपनी कोरोना वैक्सीन की पूरी जानकारी साझा करने के लिये तैयार है। मित्रेव ने हाल ही में फौसी के बयान, जिसमें उन्होंने रूस की कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा तथा क्षमता पर संदेह जताया था, का जवाब देते हुये कहा''अगर वह हमें बुलाते हैं तो हम उन्हें वैक्सीन के बारे समझाकर खुश होंगे और मुझे लगता है कि यह उनके लिये सबसे अच्छा है कि वह इसका अध्ययन करें, यह समझने के लिये कि यह कैसे काम करती है। मुझे उम्मीद है कि फाउसी उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो वास्तव में अमेरिका-रूस के बीच एक बड़े गैप को भर सकते हैं, अगर वह राजनीतिक नहीं हैं और रूस की वैक्सीन को थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करें तो।'' उल्लेखनीय है कि रूस ने स्पूतनिक वी नाम से कोरोनो वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन पंजीकृत की है, जिसे गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा 11 अगस्त को विकसित किया गया था। यह वैक्सीन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रोटोकॉल के मुताबिक आवश्यक तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों को पूरा कर रहा है।

रूस का समझौता व्यर्थ ! आर्मीनिया-आजरबैजान में तोड़ा संघर्ष विराम, फिर शुरू की खूनी जंग

येरेवान.

आर्मीनिया और आजरबैजान ने रूस की मदद से संघर्ष विराम समझौता प्रभावी होने के बावजूद सोमवार को नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र में फिर खूनी जंग शुरू कर दी। इस ताजे संघर्ष में भी कई लोगों की मौत हो गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हस्तक्षेप के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में एक संघर्षविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की देखरेख में मास्को में वार्ता के बाद शनिवार दोपहर को संघर्षविराम प्रभावी हुआ था। इस समझौते में तय किया गया था कि संघर्षविराम से संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, लेकिन ये संघर्षविराम टिक नहीं पाया। संघर्षविराम गत शनिवार को लागू हुआ था लेकिन दोनों पक्षों की इसके तुरंत बाद इसके उल्लंघन करने के दावे किये गए। यह सप्ताहांत और सोमवार सुबह तक जारी रहा। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता शुशान स्टीपैनियन ने सोमवार को कहा कि आजरबैजानी बल संघर्ष वाले %दक्षिणी मोर्चे पर व्यापक गोलीबारी कर रहे हैं। % इस बीच आजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि आजरबैजान संघर्षविराम का पालन कर रहा है लेकिन आर्मीनियाई बल आजरबैजान के गोरनबॉय, तेरतेर और अगदम क्षेत्रों पर गोलाबारी कर रहे हैं जो कि नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र के आसपास स्थित हैं। आजरबैजान और आर्मीनिया की सेनाओं के बीच हालिया लड़ाई 27 सितंबर को शुरू हुई थी और नागोर्नो-काराबाख को लेकर इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। यह इलाका आजरबैजान में आता है, लेकिन इस पर आर्मीनिया समर्थित आर्मीनियाई जातीय समूहों का नियंत्रण है।

सीमा विवाद पर राजनाथ के बयान से तिलमिलाया PAK, जमकर निकाली भारत के खिलाफ भड़ास

इस्लामाबाद:

सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तान और चीन एक मिशन के तहत भारत के साथ सीमा विवाद पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर-जरूरी और गैर-जिम्मेदाराना करार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी ये दिखाती कि उनकी सरकार पाकिस्तान को लेकर कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान-चीन की दोस्ती के खिलाफ भारत के कथित प्रोपेगैंडा की भी आलोचना की। पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा देश जो विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, उसका दूसरे देशों पर ऐसे आरोप लगाना हास्यास्पद है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वैश्विक समुदाय को अंदाजा है कि आरएसएस-भाजपा की मौकापरस्त सरकार क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। भारत खुद न केवल पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद पैदा कर रहा है बल्कि उनके शांतिपूर्ण समाधान से भी दूर भाग रहा है। पाकिस्तान ने कहा, क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में डालने, हिंदू अतिवादियों और अखंड भारत की विचारधारा को उपकरण के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय भारत को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए। भारत को अपना आक्रामक एजेंडा छोड़कर पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी सोमवार को कश्मीर को लेकर अपनी भड़ास निकाली। कुरैशी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत के नैरेटिव का सही तरीके से काउंटर किया और उनकी विदेश नीति सफल रही। कुरैशी ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मीडिया भारत के नैरेटिव पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर रहा है बल्कि वो उससे सवाल पूछ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

जल क्षेत्र में चीन की घुसपैठ जारी, जापान ने दर्ज कराया विरोध

इंटरनेशनल डेस्क: चीनी तटरक्षक बलों के दो जहाजों के विवादित पूर्व चीन सागर द्वीपसमूह से लगे जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश करने और मंगलवार तक लगातार तीसरे दिन वहां से हटने से इंकार करने के बाद जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है । इसकी जानकारी जापानी अधिकारियों ने दी । जापानी तटरक्षक अधिकारियों ने बताया कि चीन के दो जहाज जापान के दावे वाले जलक्षेत्र में रविवार की सुबह घुस गए और मछली पकड़ने वाली जापानी नौका के पास जाने का प्रयास किया जिस पर चालक दल के तीन लोग सवार थे । उन्होंने बताया कि वे अब भी वहां बने हुये हैं और वहां से निकलने की जापानी अधिकारियों के निर्देश एवं चेतावनी को अनसुना कर रहे हैं । चीनी तट रक्षक जहाज नियमित तौर पर जापान के नियंत्रण वाले दक्षिणी सेंकाकू द्वीप के आस पास जल क्षेत्र का उल्लंघन करते रहते हैं। इस क्षेत्र पर चीन भी दावा करता है और इसे दिआओयू बताता है । मुख्य कैबिनेट सचिव कत्सुनोबू कातो ने मंगलवार को कहा कि यह दुखद है कि चीनी तटरक्षक बलों का दो जहाज जापानी जलक्षेत्र में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जापान चीन से इसका सख्त विरोध करता है और मांग करता है कि चीनी जहाज तत्काल जापानी जल क्षेत्र से निकल जायें । उन्होंने कहा कि जापान अपने जल, थल और वायु क्षेत्र का बेहद मजबूती से बचाव करेगा। जापानी तट रक्षक अधिकारियों ने कहा कि चालक दल के तीन सदस्यों के साथ मछली पकड़ने वाली नौका पूरी तरह सुरक्षित है।

भारी कर्ज बावजूद इतने नोट क्यों छाप रही पाकिस्तान की इमरान सरकार?

इंटरनेशनल डेस्क: बर्बाद होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज के बावजूद पाकिस्तान में नोटों (Currency) की छपाई तेजी से हो रही है। इस समय जहां पाकिस्तान सरकार फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) के निर्देशों का अनुपालन और देश के डिजिटलीकरण की कोशिशे कर रही है, वहीं करेंसी नोटों की मांग बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में नोटों की संख्या में 1.1 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान में यह वृद्धि असामान्य है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर नोटों की संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है कि सरकार ने पुराने नोटों को नए नोटों के साथ बदल दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए नोटों की छपाई भी की है। जानकारों के अनुसार, बाज़ार में नोटों की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए, नए नोटों को सामान्य रूप से छापा जाता है, जिससे कुछ वृद्धि होती है। लेकिन असाधारण वृद्धि का मतलब है कि बहुत सारे नोट छापे गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले आठ वित्तीय वर्षों में प्रचलन में रही मुद्रा के आंकड़ों चौंकाने वाले हैं। वित्त वर्ष 2012 के अंत में चलन में रही मुद्राओं की संख्या 1.73 ट्रिलियन थी जो पिछले वित्तीय वर्ष 2020 में असामान्य वृद्धि के बाद 6.14 ट्रिलियन के स्तर पर बंद हुई। स्पष्ट है कि सरकार अधिक मुद्रा छाप रही है, जिसके कारण यह वृद्धि देखने में आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक करंसी नोटों के लिए कागज का उत्पादन करने वाली कंपनी सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड (एसईपीएल) ने हाल ही में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। कंपनी के अधिकारियों ने इस सप्ताह एक कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बताया कि एसईपीएल को वित्त वर्ष 2019-20 में 1.27 बिलियन का फायदा हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष से 65.3% अधिक था। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी का लगभग 9.2% का बजट घाटा दर्ज किया, जबकि लक्ष्य 7त्न का था। मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर क़ैसर बंगाली के मुताबिक जब सरकार को बजट की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वह नए मुद्रा नोटों को छापकर अपने खर्चों को पूरा करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ किए गए एक समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन नहीं सकती और अब वो कमर्शियल बैंकों से ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से पैसा इकट्ठा रही है, जिसकी वजह से नए नोट छापे जा रहे हैं।

पाकिस्तानी असंतुष्टों ने देश की कई समस्याओं के लिये सेना पर आरोप मढ़ा

वाशिंगटन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 'सैन्य कठपुतली' करार देते हुए पूर्व और मौजूदा सांसदों समेत प्रमुख पाकिस्तानी असंतुष्टों ने देश में स्थायित्व न होने, असुरक्षा और पड़ोसियों के साथ चलने की अक्षमता के लिये शक्तिशाली सेना को आरोपी ठहराया।पश्तून नेता और पूर्व सेनेटर अफरासियाब खटक ने 'साउथ एशियन अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स' (एसएएटीएच) के पांचवें वार्षिक सम्मेलन में कहा, 'पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लागू है।' एसएएटीएच लोकतंत्र समर्थक पाकिस्तानियों का एक समूह है जिसकी स्थापना अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी और अमेरिका स्थित स्तंभकार डॉ. मोहम्मद तकी ने की थी। एक बयान के मुताबिक पूर्व में एसएएटीएच के वार्षिक सम्मेलन लंदन और वाशिंगटन में हुए थे लेकिन इस बार सम्मेलन में प्रतिभागी डिजिटल तौर पर शामिल हुए। इसमें कहा गया कि प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री खान को एक 'सैन्य कठपुतली' करार दिया।

अमेरिका में कोलंबस दिवस का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट व लिंकन की प्रतिमाएं तोड़ीं

न्यूयार्क: कोलंबस दिवस के विरोध में अमेरिका के पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपतियों थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन की प्रतिमाओं को तोड़कर गिरा दिया और ओरेगन हिस्टोरिकल सोसाइटी में तोड़फोड़ की। 15वीं शताब्दी के इतालवी खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर सोमवार के संघीय अवकाश के जवाब में प्रदर्शन आयोजकों ने इसे 'इंडीजेनस पीपल्स डे ऑफ रेज' करार दिया। अमेरिका के मूल निवासियों के अधिकारों के पैरोकारों का कहना है कि कोलंबस ने धुवीकरण किया और अमेरिका में स्वदेशी आबादी के खिलाफ उस नरसंहार को हवा दी जो अब सदियों से चला आ रहा है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, रविवार रात प्रदर्शनकारियों के समूह ने रूजवेल्ट की प्रतिमा के चारों ओर जंजीरें बांध दीं और प्रतिमा का नाम 'थियोडोर रूजवेल्ट, रफ राइडर' रख दिया। उन्होंने स्मारक पर लाल पेंट फेंका । रात के नौ बजे से कुछ ही देर पहले मूर्ति को भीड़ ने नीचे गिरा दिया। समूह ने बाद में लिंकन की प्रतिमा की ओर रुख किया और इसके लगभग आठ मिनट बाद उसे भी नीचे गिरा दिया।

कोरोना वायरस: संक्रमण के बाद महीनों तक रहता है बीमारी का असर

वाशिंगटन।

कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीजों में कई सप्ताह एवं महीनों तक इसके लक्षण नजर आते हैं और विशेषज्ञों के लिए यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि मरीज कितने समय बाद पूरी तरह स्वस्थ महसूस करेंगे। जिन मरीजों में संक्रमण के मामूली लक्षण होते हैं, वे जल्द ही इस बीमारी से उबर जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग और गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को कई बार स्वस्थ होने में तीन-चार महीने भी लग जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि आमतौर पर मरीज दो सप्ताह से छह सप्ताह में स्वस्थ हो जाते हैं। अमेरिका के एक अध्ययन के अनुसार, मामूली लक्षण वाले जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, उनमें से 20 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिनमें संक्रमित होने के कम से कम दो सप्ताह बाद भी बीमारी के लक्षण थे। इटली में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, अस्पताल में भर्ती मरीजों में से 87 प्रतिशत लोगों में संक्रमित होने के दो महीने बाद भी थकान और सांस लेने में परेशानी समेत संक्रमण के लक्षण थे। शिकागो में फेफड़ों संबंधी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉ. खालिलाह गेट्स ने कहा कि उनके कई मरीजों में

संक्रमित होने के चार महीने बाद भी बीमारी के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि यह बताना बहुत मुश्किल है कि कोई मरीज पूरी तरह स्वस्थ कब महसूस करेगा। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. जय वार्के ने कहा, च्च्आप गंभीर बीमारी से भले ही उबर चुके हों, लेकिन जरूरी नहीं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए हों।

चीन बढ़ा रहा किलर मिसाइलों से लैस परमाणु सबमरीन की फौज, बढ़ेगी भारत-अमेरिका की टेंशन

बीजिंग:

चीन की दुनिया पर कब्जा करने की नीयत और आक्रमकता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ड्रैगन ने ब्लू वॉटर नेवी बनने के लिए अपनी पूरी ताकत अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों पर लगा दी है। चीन इसके लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने वाले अपने एकमात्र शपियार्ड का व्यापक विस्तार कर रहा है। सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने परमाणु पनडुब्बी सीमित निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस ली है। चीन की इस तैयारी को देखते हुए अमेरिका और भारत की टेंशन बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक सैटलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अपने शिपयार्ड का बड़े पैमाने पर अतिरिक्त विस्तार कर रहा है। इस विस्तार के काम के पूरा होने के बाद चीन बड़े पैमाने पर परमाणु पनडुब्बी बनाने लगेगा। यही नहीं इस विस्तार के बाद चीनी शिपयार्ड के परमाणु सबमरीन बनाने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। चीन अगले 10 साल में परमाणु पनडुब्बी निर्माण के मामले में दुनियाभर में चर्चा का विषय बना रहेगा। द ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के हमलावर परमाणु पनडुब्बियों की संख्या वर्ष 2030 तक बढ़कर 6 हो जाएगी। वहीं अन्य विश्लेषकों का कहना है कि चीन के इन परमाणु पनडुब्बियों की संख्या और ज्यादा हो सकती है। सैटलाइट की तस्वीरों से खुलासा है कि हुलुदाओ में बोहाई शिपयार्ड में एक नए निर्माण हाल का निर्माण किया जा रहा है। यही पर चीन ने वर्ष 2015 में एक बेहद अत्याधुनिक पनडुब्बी का निर्माण किया था। नए हाल में एक साथ दो पनडुब्बियों के निर्माण की सुविधा होगी। हाल ही में यहां पर कुछ और हाल बनाए गए हैं जिससे एक साथ एक छत के नीचे 4 पनडुब्बी बनाई जा सकेंगी। इसी स्थल के दूसरी ओर एक और निर्माण स्थल है जो अभी भी सक्रिय है। इसका मतलब है कि चीन एक बार में 4 से 5 पनडुब्बियों का निर्माण कर सकता है। परमाणु पनडुब्बियों में बलस्टिक मिसाइल सबमरीन और अटैक सबमरीन दोनों ही शामिल हैं। इन्हें घातक मिसाइलों से लैस करने की चीन की योजना है। चीन की यह तैयारी अमेरिका और भारत के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका के रक्षामंत्री मार्क ईस्पर ने कहा है कि चीन से टक्कर के लिए बनाई जा रही बैटल फोर्स 2045 के तहत हमें जल्द से जल्सद हर साल वर्जीनिया क्सलास की तीन परमाणु सबमरीन बनाना होगा। ये विशाल और ज्यादा ताकतवर सबमरीन 70 से 80 की संख्सया में बनाई जानी हैं। इसे भविष्सय में महाशक्तियों की जंग में सबसे ज्यादा कारगर हमलावर हथियार माना जा रहा है। उधर, चीनी नौसेना की नजर अब हिंद महासागर पर भी हो गई है। चीन ग्वादर में नेवल पोर्ट बना रहा है और उसका एक पोर्ट पहले से ही अफ्रीका के जिबूती में है। चीन के नौसेना की उपस्सथिति भी अब हिंद महासागर में लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के इसी खतरे को देखते भारत की टेंशन बढ़ गई है।

बैरेट के मनोनयन पर जोर देकर रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी लोगों की इच्छा को नकार रही : हैरिस

वाशिंगटन.

अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने आरोप लगाया है कि उच्चतम न्यायालय के लिए न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट के मनोनयन के लिए सीनेट से मंजूरी में जल्दबाजी कर रिपब्लिकन पार्टी लोगों की इच्छा की अवज्ञा कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित होने तक यह प्रक्रिया स्थगित कर दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति रूथ बेडर जिन्सबर्ग के स्थान पर न्यायाधीश बैरेट को चुना है। जिन्सबर्ग का पिछले दिनों निधन हो गया था। उच्चतम न्यायालय की मंजूरी के लिए सोमवार को न्यायाधीश बैरेट की बहस के दौरान हैरिस ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रक्रिया जारी रखने की आलोचना की। न्यायपालिका समिति में शामिल दो सीनेटरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। हैरिस ने कहा कि सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी उच्चतम न्यायालय में बैरेट की नियुक्ति के लिए सीनेट से मंजूरी की प्रक्रिया में जल्दबाजी कर रही है जबकि तीन नवंबर को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ तीन सप्ताह दूर है। वह सीनेट की न्यायपालिका समिति की एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक सदस्य हैं। वह अपने कार्यालय से ही समिति की बैठक में शामिल हुयीं। हैरिस ने अपने चुनाव अभियान से समय निकालते हुए कहा '' अमेरिका के 90 लाख से अधिक लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं और लाखों अन्य लोग मतदान करेंगे जबकि ÷समिति की यह अवैध प्रक्रिया चल रही है।''

भारत-चीन विवाद: सातवें दौर की वार्ता में दोनों पक्षों ने दिया शांति बनाए रखने पर जोर

नई दिल्ली:

भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले पांच महीने से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत के जरिये सैनिकों को पीछे हटाने सहित टकराव के सभी मुद्दों का जल्द से जल्द सर्वसम्मत समाधान खोजने पर सहमति जतायी है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच सोमवार को सातवें दौर की बातचीत के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और मैत्रीपूर्ण माहौल बनायेंगे तथा मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देंगे। भारतीय सीमा के चुशूल क्षेत्र में सोमवार को करीब बारह बजे शुरू हुई बैठक में सेना का प्रतिनिधित्व 14 वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल पी जी के मेनन भी थे जिन्होंने आज ही इस कोर के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें ले जनरल सिंह के स्थान पर यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है। ले जनरल सिंह को सैन्य अकादमी देहरादून की कमान सौंपी गयी है। इन दोनों के साथ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी भी बातचीत के दौरान मौजूद थे। दोनों पक्षों के बीच गत 21 सितम्बर को हुई छठे दौर की बातचीत में भी ले जनरल सिंह तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। बयान कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच जारी सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ तैनात सैनिकों को हटाने के मुद्दे पर गंभीरता से व्यापक और रचनात्मक बातचीत हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और उनका कहना है कि बातचीत सकारात्मक, रचनात्मक रही और दोनों ने एक दूसरे के रूख को अच्छी तरह से समझा है। बयान में कहा गया है कि भारत और चीन दोनों ने ही इस बात पर सहमति जतायी है कि वे सैनिकों को पीछे हटाने के मुद्दे का जल्द से जल्द सर्वसम्मत समाधान निकालने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर संवाद तथा संपर्क बनाये रखेंगे।दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वे दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण समझ पर आधारित बातों को लागू करेंगे, मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देंगे और सीमा पर शांति तथा मैत्रीपूर्ण माहौल के लिए मिलकर काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि मई में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की कोशिशों के कारण दोनों पक्षों के बीच पिछले पांच महीने से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। इसी दौरान दोनों ओर के सैनिकों के बीच गत 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हुई जिसमें भारत के एक कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गये। चीन के भी बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हालाकि उसने सार्वजनिक रूप से कभी यह स्वीकार नहीं किया। इस झड़प के बाद सीमा पर बढे तनाव को कम करने के लिए सैन्य , राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच भी बातचीत हुई है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि गतिरोध को बातचीत के जरिये दूर किया जाना चाहिए लेकिन निरंतर हो रही बातचीत का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ रहा है। दोनों ओर के सैनिकों की

वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ तैनाती टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर खास प्रगति नहीं हो सकी है। सातवें दौर की बातचीत में भी इस मुद्दे पर किसी प्रगति की बात नहीं कही गयी है। भारत ने चीन पर निरंतर इस बात को लेकर दबाव बनाया हुआ है कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल की यथास्थिति कायम करे और अपने सैनिकों को पीछे हटाए।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आज जिस तेजी से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से इस दवा उद्योग का भी विस्तार हो रहा है. इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हमेशा ही मौजूद हैं. दुनिया की विशाल आबादी के बीच औषधि का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है. औषधि उद्योग, जिसे फार्मा इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, का विस्तार उदारीकरण के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिकल ट्रायल, जेनेटिक ड्रग तक हो चुका है.

रोजगार के द्वार खोलती फार्मा इंडस्ट्री

फार्मा में बढ़ रही है मांग

दवाओं के वितरण से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग और मैनेजमेंट सभी फार्मास्यूटिकल के अहम हिस्से हैं. इसमें भारत की भागीदारी अहम है. ज्यादातर कंपनियों को यहां अपने उद्योग को बढ़ाने और फलने-फूलने का मौका मिलता है. एक अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में आज तकरीबन पांच लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है. आए दिन इस क्षेत्र की जिस तरह से तरक्की हो रही है, उसमें फार्मा विशेषज्ञ और इससे जुड़े लोगों की मांग और बढ़ेगी.

इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही देशभर में कुशल या दक्ष फार्मासिस्ट तैयार करने के लिए जगह- जगह फाम्रेसी के कॉलेज खोले जा रहे हैं. पहले से भी सरकारी स्तर पर जिला और राज्य स्तर पर फार्मेसी कॉलेज चल रहे हैं. उनमें डिग्री, डिप्लोमा से लेकर रिसर्च का काम हो रहा है. कार्य क्षेत्र सामान्य उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जहां सीधे डीलर या कस्टमर से संपर्क करना होता है, वहीं दवाओं की मार्केटिंग में डॉक्टर भी अहम कड़ी होता है. दवाओं के बारे में डॉक्टरों को संतुष्ट करना जरूरी है, तभी वे इसे मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं. कौन सी दवाएं किस रोग के इलाज में असरदार होंगी, इसका ज्ञान औषधि विशेषज्ञ के पास ही होता है. उसे रिसर्च करके आए दिन नई-नई दवाएं और ड्रग्स भी विकसित करने पड़ते हैं. इसलिए फार्मा मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए दवाओं की बिक्री के साथ-साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले पदार्थ व तकनीक के ज्ञान की भी अपेक्षा होती है.

इस तरह के हुनर से लैस लोगों को दवा के निर्माण, मार्केटिंग से लेकर वितरण तक अपनी भूमिका निभानी पड़ती है. फार्मासिस्ट को अस्पतालों में, डिस्पेंसरी और मेडिकल स्टोर में इस काम के लिए विशेष रूप से रखा जाता है. इसके अलावा बाजार में जगह बनाने के लिए बतौर मेडिकल रिप्रजेंटेटिव और मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में आगे आना पड़ता है.

मेडिकल साइंस से जुड़े विषय की करें पढ़ाई

दाखिले की प्रक्रिया इस क्षेत्र में आने के लिए 10वीं से ही खुद को दिमागी तौर पर तैयार रखना पड़ता है क्योंकि इसमें 12वीं के अंकों के आधार पर उन्हीं छात्रों को दाखिला दिया जाता है जिन्होंने मेडिकल साइंस से जुड़े विषय की पढ़ाई की है.

छात्रों को न्यूनतम पचास फीसद अंक के साथ बारहवीं में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जूलॉजी आदि विषय पढ़ा होना चाहिए. कोर्स की पढ़ाई के लिए मेडिकल साइंस और बायोलॉजी में रुचि और उसकी समझ होना जरूरी है. इसके अलावा इनोवेटिव आइडिया की भूमिका अहम है. अनुसंधान यानी जांच-पड़ताल की समझ होना जरूरी है. वेतनमान बीफार्मा की डिग्री धारकों को आमतौर पर बाजार में 25 से 30 हजार की नौकरी मिल जाती है. इसमें जो छात्र डिप्लोमा करते हैं उन्हें मेडिकल सेंटर या केमिस्ट शॉप पर सेल्स व मार्केटिंग के काम में शुरुआती स्तर पर 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते हैं. रिसर्च स्तर के छात्रों को 30 से 40 हजार प्रतिमाह पैकेज दिया जाता है. सस्ती व प्रभावी दवाएं चिकित्सा जगत में हाथों-हाथ ली जाती हैं. पुरानी दवाओं में भी समय रहते सुधार कर सकते हैं. काफी मेहनत के बाद पहचान मिलती है. दवाओं और ड्रग्स का निर्माण या विकास भी इस क्षेत्र में काफी हुनर की अपेक्षा रखता है.

विभिन्न कोर्स

डिप्लोमा इन फाम्रेसी बैचलर इन फाम्रेसी बीबीए फार्मा मैनेजमेंट एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट मास्टर इन फाम्रेसी पीएचडी इन फार्मेसी क्या है. सिलेबस फाम्रेसी से जुड़ा डिप्लोमा कोर्स दो साल का है. इसमें छात्रों को फाम्रेसी से जुड़ी आधारभूत चीजें बताई जाती हैं. बीफार्मा चार साल का बैचलर डिग्री कोर्स है. इसमें चार साल के अंदर औषध विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों को विस्तार से बताया जाता है. बीफार्मा के बाद पीजी लेवल पर एमफार्मा में स्पेशलाइजेशन का दौर शुरू हो जाता है. इसमें छात्रों को फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल फाम्रेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी सुधार प्रोग्राम, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रूप से दक्ष बनाया जाता है. पीएचडी में दवाओं और ड्रग्स को लेकर अनुसंधान का काम करना होता है.

संभावनाएं

फाम्रेसी का कोर्स करने के बाद रिसर्च एंड डे वलपमेंट में नौकरी पा सकते हैं. साथ ही फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स व मार्केटिंग का काम कर सकते हैं. जनसंख्या के अनुपात में बीमारियों की बढ़ोतरी से फार्मा इंडस्ट्री का विस्तार हो रहा है. आज निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक देश के कोने-कोने में खोले जा रहे हैं. सरकारी अस्पताल का भी विस्तार हो रहा है. ऐसे में इन क्षेत्रों में फार्मा स्पेशलिस्ट की मांग काफी है. मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट के रूप में छात्रों को रखा जाता है. भारत में इस समय 23 हजार से भी अधिक रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं. इनमें से करीब 300 ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में हैं. अनुमान के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब पांच लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है. मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेस अधिकारी व एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन केमिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल और इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव जैसे पद पर निजी कंपनियों में काम करने का मौका मिलता है. एमफार्मा करने के बाद साइंटिस्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद पा सकते हैं. फार्मेसी कॉलेज में अध्यापन का काम भी कर सकते हैं. रिसर्च और दवा निर्माता कंपनियों में प्रोडक्शन के काम से जुड सकते हैं.

अवसरों के द्वार खोलने को तैयार नैनो टेक्नोलॉजी

नैनो टेक्नोलॉजी को भविष्य की तकनीक भी कहा जाता है. 21वीं सदी में साइंस के कदम जिस ओर सबसे अधिक बढेंगे, उनमें नैनो साइंस एक है. इस क्षेत्र में करियर और काम करने की अपार संभावनाओं को देखते हुए ही देश के कई कॉलेज और संस्थान अपने यहां नैनो टेक्नोलॉजी का कोर्स चलाने लगे हैं. कहीं यह सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में है तो कहीं डिप्लोमा या डिग्री के रूप में. इस कोर्स को कराने का मकसद छात्रों को नैनोमैटीरियल्स और नैनो टेक्नोलॉजी के प्रायोगिक और सैद्धांतिक पहलू से रू-ब-रू कराना होता है. इस क्षेत्र में रिसर्च की संभावनाओं को बढ़ावा देना है. दिल्ली विश्वविद्यालय में इन संभावनाओं को देखते हुए ही नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में एमटेक का तीन वर्षीय कोर्स पांच साल पहले शुरू किया गया था.

कोर्स में क्या है

कोर्स में छात्रों को पहले पहल नैनो स्केल साइंस और तकनीक से परिचय कराया जाता है. प्राचीन भारत में भारतीय मेडिसिन में इसका रोल क्या रहा है और उसके नैनो टेक्नोलॉजी में साइंस का फंडामेंटल क्या है, इसकी जानकारी दी जाती है. इसके तहत इलेक्ट्रांस, आयंस, एटम्स, मैटीरियल सहित फोटोंस आदि के साथ इंटरएक्शन दिखाया जाता. इसमें मैटीरियल साइंस की पढ़ाई भी कराई जाती है. यहां नैनो मैटीरियल के उद्योगों में नैनो मैटीरियल्स के प्रयोग के बारे में बताया जाता है. कोर्स में थियरी पेपर और लैबोरेटरी वर्क और प्रोजेक्ट वर्क का काम भी कराया जाता है. छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क किसी उद्योग, रिसर्च संस्थान और प्रयोगशाला में करना होता है. उसके कार्य का विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं.

नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

देश-विदेश में एटमोस्फेयर, एयरोस्पेस टेली कम्यु निकेशन, सौर ऊर्जा, कंप्यूटिंग, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल चल रहा है.

इस क्षेत्र में काम करने वालों ने नैनो की मदद से ऐसा फैब्रिक बनाया है, जिसके बने कपड़े पर किसी रसायन या जैविक हमले का असर नहीं होगा. इसको आग और पानी से नुकसान नहीं पहुंचेगा. इन रिसर्चरों ने ऐसी तकनीक भी बनाई है जिससे पर्यावरण में आने वाले बदलाव को समझा जा सके. इस क्षेत्र में बायो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे कण बनाए गये हैं जो शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में दवा पहुंचाने का काम करेगी.

दाखिले की प्रक्रिया

दिल्ली विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन का काम 28 जून तक चलेगा. कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया दो तरह से आयोजित की जाती है. पहला आईआईटी में रसायन और भौतिकी में एमएससी में दाखिले के लिए आयोजित जैम यानी संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्र यहां आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, इस कोर्स में उन छात्रों को भी दाखिले का मौका दिया जाता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एमएससी प्रवेश परीक्षा में अव्वल आते हैं. इनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं. कुल 15 सीटें हैं. आवेदन के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है. इसके बाद छात्रों की लिस्ट लगाई जाती है. इस कोर्स में अन्य संस्थान भी आमतौर पर दाखिला उन्हीं छात्रों को देते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस का हैं तथा जिन्होंने 12वीं में भौतिकी, रसायन, गणित और जीव विज्ञान पढ़ा है और ग्रेजुएशन भी साइंस से किया है. इससे जुड़े कोर्स में दाखिला कहीं एप्टीट्यूट टेस्ट पर तो कहीं मेरिट के आधार पर होता है. आईआईटी में इसकी पढ़ाई हो रही है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलूर, इं द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे कई नामचीन संस्थान भी इससे जुड़े कोर्स चला रहे हैं.

करियर की संभावनाएं

इस कोर्स को करने वालों के लिए आज विभिन्न सेक्टरों में ढेरों अवसर सामने हैं. वे चाहें तो नैनो-मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर सकते हैं. स्टेम सेल डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, नैनो-टॉक्सिकोलॉजी आदि कई ऐसे क्षेत्र है जहां काम करने का मौका मिलेगा. सीएसआई यानी काउंसिल ऑफ साइं टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने देशभर में 38 लैबारेटरी बनायी हैं जहां इस क्षेत्र में अनुसंधान और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जा सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, छात्रों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के भी कई अवसर हैं. भारत सरकार ने साइंस में इसका रोल समझते हुए विज्ञान और तकनीक विभाग में एक अलग शाखा के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी को स्वीकृति दी है. अभी इस साइंस के विशेषज्ञ बहुत कम हैं इसलिए नौकरी आसानी से मिल जाती है.

फिजियोथैरेपी से संवारें अपना भविष्य

फिजियोथैरेपी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शारीरिक व्यायाम और कुछ मशीनरी के सहयोग से हड्डियों और मांसपेशियों की बीमारियों को ठीक किया जाता है. आज हाईटेक लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोगों को हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याएं ज्यादा होती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में इलाज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. फलस्वरूप रोजगार का आगाज भी तेजी से हो रहा है. फिजियोथैरेपी, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शारीरिक व्यायाम और कुछ मशीनरी सहयोग से हड्डियों और मांसपेशियों की बीमारियों को ठीक किया जाता है. इसके सहयोग से निष्क्रिय पड़ी मांसपेशियों को क्रियाशील बनायी जाती है. फलस्वरूप, रोजगार का आगाज भी तेजी से हो रहा है. उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया में दवाइयों का सेवन लगभग न के बराबर होता है, अत- इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है. चूंकि यह प्रक्रिया एक्सरसाइज और मशीनरी के सहयोग से पूरी की जाती है, अत- इसका लाभ भी ज्यादा होता है. इस तकनीक के विशेषज्ञ को फिजियोथैरेपिस्ट कहते हैं. फिजियोथैरेपी के सहयोग से शरीर की क्रियान्वयन क्षमता बढ़ती है. इसका प्रयोग ज्यादातर शारीरिक रूप से कमजोर लोगों, स्पोर्ट्सपर्सन, हड्डियों की समस्या से जूझ रहे लोगों और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है. प्रमुख शिक्षण संस्थान- गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली निजाम इंस्टीट्यू ट ऑफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद.

पाठ्यक्रम – इस क्षेत्र में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर की पढ़ाई होती है. इसके अलावा, इसमें पीएचडी भी होती है. बैचलर स्तर के कोर्स को बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी यानी बीपीटी कहते हैं जबकि पीजी स्तर पर मास्टर ऑफ फिजियोथैरेपी यानी एमपीटी का कोर्स किया जाता है. इसके अलावा, कुछ शिक्षण संस्थान डिप्लोमा कोर्स भी कराते हैं. सामान्यत- स्नातक स्तर का कोर्स साढ़े चार साल का होता है जिसमें अंतिम छह महीने इंटर्नशिप के होते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स दो साल का होता है. इसके अंतर्गत, न्यू रो लॉजिकल, फिजियोथैरे पी, स्पोर्ट्स फिजियोथैरेपी, पेडियाट्रिक फिजियोथैरेपी आदि में विशेषज्ञता हासिल की जाती है. इसके अलावा, ऑनलाइन कोर्स भी इस क्षेत्र में उपलब्ध है. इन पाठ्यक्रमों के तहत, मूवमेंट साइंस, आर्थोपेड्रिक्स, न्यूरोलॉजिकल साइंस आदि के बारे में अध्ययन कराया जाता है.

योग्यता – इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के लिए बारहवीं में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमेस्ट्री में उत्तीर्ण होना जरूरी है. नौकरियां इसमें सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों में रोजगार के अवसर हैं. अस्पतालों, मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्पोर्ट्स एकेडमी, फिटनेस सेंटर में नौकरी की तलाश की जा सकती है. साथ ही, स्वयं का फिजियोथैरेपी सेंटर भी खोला जा सकता है. शिक्षण संस्थान में बतौर प्राध्यापक भी काम कर सकते हैं. व्यक्तिगत गुर इसमें लोगों की समस्याओं को समझने का हुनर होना जरूरी है. धैर्य होने की काफी जरूरत है क्योंकि इस सेक्टर में इलाज के लिए वही आता है जो अपनी बीमारी से आजिज हो चुका होता है. इसमें धैर्य की भी काफी जरूरत होती है. एक्सरसाइज कराने का सही तरीका आना जरूरी है ताकि इलाज में आसानी रहे.

आमदनी – इस सेक्टर में अनुभव के आधार पर लाख रुपये तक मासिक आमदनी की जा सकती है. वैसे तो बतौर, ट्रेनी फिजियो के तौर पर बारह से पंद्रह हजार की सेलरी मिल सकती है. इसके अलावा, स्वयं के निजी सेंटर से सिटिंग के आधार पर दो सौ से पांच सौ रुपये प्रतिघंटे कमाया जा सकता है. प्राध्यापक के तौर पर पचास हजार से एक लाख रुपये तक की मासिक आमदनी संभव है.

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वित्त मंत्री की घोषणाएं 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', आर्थिक पैकेज विफल : चिदंबरम

नयी दिल्ली। (एजेंसी)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त कर्ज देने समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' करार देते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार ने अपने 20 लाख करोड़ रुपये के 'तथाकथित आर्थिक पैकेज' की विफलता को स्वीकार किया है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह दावा भी किया कि सीतारमण की घोषणाएं कोई प्रोत्साहन पैकेज नहीं, बल्कि आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हुए लोगों को चौंकाने एवं तसल्ली देने की कोशिश भर है। चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ''तथाकथित प्रोत्साहन पैकेज के बारे में वित्त मंत्री के बयान को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे हिंदी की कहावत 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' याद आ गई।'' उन्होंने कहा, ''वित्त मंत्री ने सोमवार को जो बड़ी घोषणाएं कीं वो कोई प्रोत्साहन पैकेज नहीं था। यह आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके लोगों को चौंकाने और यह विश्वास दिलाने का प्रयास है कि लोगों की जरूरत और अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार कदम उठा रही है।''

पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया, ''यह इस बात का ठोस कबूलनामा है कि 20 लाख करोड़ रुपये का तथाकथित आर्थिक पैकेज बहुत बड़ी विफलता था। यह विफल था क्योंकि यह धोखा था।'' चिदंबरम के मुताबिक, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की अग्रिम राशि देने की घोषणा की है जो कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है। इसे 10 मासिक किस्तों में वसूल लिया जाएगा। यह एक तरह की ईएमआई है। उन्होंने कहा, '' राज्यों को जिस 12 हजार करोड़ रुपये को देने की पेशकश की गई वो अनुदान नहीं, बल्कि कर्ज है। सभी बड़े राज्यों को 7500 करोड़ रुपये मिलेंगे जो मौजूदा वित्त वर्ष में उनके कुल पूंजीगत खर्च नौ लाख करोड़ रुपये की तुलना में कुछ भी नहीं है। इससे बहुत कम फर्क पड़ेगा।'' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया, ''केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी पर कर की रियायत देने की पेशकश कर्मचारियों से उनका अपना ही पैसा कर के मामूली फायदे के लिए दो बार खर्च कराने का दयनीय प्रयास है। उन्होंने कहा, ''जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनको एक बार फिर से असहाय छोड़ दिया गया है। सरकार ने लोगों के खाते में पैसे भेजने से इनकार कर दिया जिसकी सिफारिश कई अर्थशास्त्रियों और कांग्रेस तथा दूसरे दलों ने की थी।''

गौरतलब है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने सोमवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करायेगी। कर्ज 50 साल की अवधि का होगा और यह पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिये दिया जायेगा। उन्होंने इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है। वित्त मंत्री के अनुसार, सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला भी किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया है।

सार समाचार

असम में कोरोना के मामलों का ग्राफ नीचे आ रहा है: हिमंत बिस्व सरमा

गुवाहाटी। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित होने की दर में लगातार गिरावट आने के बाद संक्रमण के मामलों का वक्र नीचे आ रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमित होने की दर सितंबर में नौ प्रतिशत से अधिक थी जो चार अक्टूबर तक घटकर 5.8 प्रतिशत रह गई। सरमा ने कहा, 'पिछले सप्ताह संक्रमित होने की दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई और सोमवार तक यह घटकर 1.8 फीसदी हो गई।' उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण के नए मामलों की संख्या में भी गिरावट आयी है, वहीं संक्रमण से मुक्त होने की दर फिलहाल 85 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा, 'पिछले 15 दिनों के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और हम कह सकते हैं कि संक्रमण के मामलों का ग्राफ नीचे की ओर आना शुरु हो गया है। हमें अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहकर सभी सावधानियां बरतनी होगी। यदि हम यह करना जारी रखते हैं तो हमें विश्वास है कि हम कोविड-19 के खिलाफ यह लड़ाई अवश्य जीत लेंगे।' उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक कुल 826 लोग कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि 1,000 से अधिक लोगों की जान अन्य कारणों से गई है। असम में फिलहाल 28,439 मरीजों का उपचार चल रहा है जबकि 1,66,036 लोग इस संक्रमण को मात दे चुके हैं।

भारत और चीन के बीच सातवें दौर की सैन्य वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक : संयुक्त वक्तव्य

नयी दिल्ली। भारत और चीन के बीच सातवें दौर की सैन्य वार्ता 'सकारात्मक और रचनात्मकफ रही तथा दोनों पक्ष अपने नेताओं द्वारा मतभेदों को विवादों में न बदलने की आपसी समझ को क्रियान्वित करने पर सहमत हुए। दोनों सेनाओं की ओर से मंगलवार को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। वास्तविक नियंत्रण के भारतीय क्षेत्र में स्थित चुशुल में लगभग 12 घंटे चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुलाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में सीमा पर पांच महीने से अधिक समय से गतिरोध की स्थिति में हैं। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के पीछे हटने पर गंभीर, व्यापक और रचनात्मक बातचीत की।' वक्तव्य में कहा गया कि दोनों पक्षों इस पर सहमत हुए कि यह वार्ता 'सकारात्मक, रचनात्मक' रही और इससे एक दूसरे की स्थिति के प्रति बनी आपसी समझ में वृद्धि हुई। वक्तव्य में कहा गया, 'दोनों पक्ष सैन्य तथा राजनयिक माध्यम से संवाद और संपर्क बरकरार रखने और यथाशीघ्र सैनिकों की वापसी के लिए दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए।

राहुल गांधी का आरोप, मोदी सरकार ने किसानों को दिया धोखा

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें सिर्फ धोखा दिया। उन्होंने अपने हालिया पंजाब एवं हरियाणा दौरे से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ''किसानों ने देश को खाद्य सुरक्षा दी और मोदी सरकार ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया। लेकिन अब और नहीं।'' पिछले दिनों कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में 'खेती बचाओ यात्रा' निकाली थी। गौरतलब है कि संसद के पिछले मानसून सत्र में दोनों सदनों ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक) 2020, किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 औरआवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुछ दिनों पहले इन विधेयकों को अपनी संस्तुति प्रदान की जिसके बाद ये कानून बन गए। इससे पहले, राहुल गांधी ने जातिगत भेदभाव संबंधी एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ''यह वीडियो उनके लिए है जो सच्चाई से भाग रहे हैं। हम बदलेंगे, देश बदलेगा।

राज्यपाल के पत्र पर संजय राउत का पलटवार, हमें हिंदुत्व पर पाठ की जरूरत नहीं है

मुम्बई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सिर्फ यह देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं तथा बाकी चीजों की देखभाल के लिए लोगों द्वारा एक निर्वाचित सरकार है। राज्य में उपासना स्थलों को खोलने को लेकर कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखने और उस पर ठाकरे के जवाब के आलोक में राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शिवेसना का हिंदुत्व दृढ है और मजबूत बुनियाद पर टिका है तथा उसे इस पर किसी से पाठ की जरूरत नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान, कि अब भी कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, का हवाला देते हुए राउत ने कहा कि स्वास्थ्य चिंता के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना ठाकरे की जिम्मेदारी है और राज्यपाल को तो यह काम अच्छी तरह करने के लिए ठाकरे की प्रशंसा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कोश्यारी ने कहा कि उन्हें प्रतिनिधिमंडलों से तीन प्रतिवेदन मिले हैं जिनमें धर्मस्थलों को खोले जाने की मांग की गयी है। उन्होंने पत्र मे लिखा है, ''क्या आप अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गये?'' राउत ने कहा, '' कोश्यारी राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। उन्हें यह देखना है कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। बाकी बातों के लिए लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है। वह निर्णय लेती है।''

कोरोना से लड रही दिल्ली प्रदुषण से कैसे बचेगी? डॉक्टर दे रही ये सलाह

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के बाद कोविड के बढ़ने की संभावना है। शहर के अस्पतालों का कहना है कि वे पहले से ही उन मरीजों को देख रहे हैं, जिन्हें कोविड -19 से सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की थी। उनमें से कई में पहले से मौजूद सांस की समस्याएं हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी)।अपोलो अस्पताल के आंतरिक सलाहकार डॉ। सुरंजीत चटर्जी के मुताबिक कोविड -19 रोगियों में से लगभग 15त्न गंभीर लक्षण विकसित करते हैं। शरीर में फेफड़े मुख्य अंगों में से एक है जो काफी प्रभावित होता है और संक्रमण के कम होने के बाद भी अंग में दिक्कतें बनी रहती है। इससे निपटने के लिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कई निजी अस्पतालों ने कोविड क्लीनिक शुरू किया है। मैक्स अस्पताल में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ। रोमेल टिकू ने कहा कि अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों में लक्षणों की अधिकता के साथ रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। बता दें कि वायु प्रदूषण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हर सर्दियों में दिखाई देता है। पारस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख डॉ। अरुणेश कुमार ने कहा कि 'हम पल्मोनोलॉजी ओपीडी में आने वाले छाती के लक्षणों के साथ रोगियों में वृद्धि देख रहे हैं। यदि आप छाती के लक्षणों को बिगड़ते हुए देखते हैं तो चिकित्सीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर इस सर्दी में आपको निमोनिया और फ्लू के टीके लगाने की सलाह मिली है तो उसे जरूर लगाए। उन्होंने कहा, 'फेस मास्क पहनना कोविड -19 से सुरक्षित रहने के साथ-साथ इस सर्दी में प्रदूषण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रदूषण के कारण आउटडोर व्यायाम से बचना भी फायदेमंद होगा। आईएमए सामाजिक संगठनों के सहयोग से दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। कार्यक्रम के संयोजक डॉ। हरीश गुप्ता ने कहा कि फेस मास्क प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में भी मदद कर सकता है।

लद्दाख गतिरोध : सातवें दौर की सैन्य वार्ता में भारत ने चीन से कहा- अपने सैनिकों को पीछे हटाओ

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के समाधान के लिए भारत ने सोमवार को चीन के साथ सातवें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिन्दुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की वार्ता दोपहर लगभग 12 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चुशूल क्षेत्र में भारतीय इलाके में हुई और रात साढ़े आठ बजे के बाद भी जारी रही। सीमा विवाद छठे महीने में प्रवेश कर चुका है और विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखते हैं क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग एक लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं जो लंबे गतिरोध में डटे रहने की तैयारी है।

वार्ता के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि एजेंडा विवाद के सभी बिन्दुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने का था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव कर रहे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वार्ता में चीनी विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में भारत ने जोर देकर कहा कि चीन को विवाद के सभी बिन्दुओं से अपने सैनिकों को जल्द और पूरी तरह वापस बुलाना चाहिए तथा पूर्वी लद्दाख में सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पूर्व की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। गतिरोध पांच मई को शुरू हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों सहित चीन अध्ययन समूह(सीएसजी) ने सैन्य वार्ता के लिए शुक्रवार को भारत की रणनीति को अंतिम रूप दिया।

सीएसजी चीन के बारे में भारत की महत्वपूर्ण नीति निर्धारक इकाई है। सातवें दौर की सैन्य वार्ता शुरू होने से पहले सूत्रों ने कहा था कि भारत पैंगोंग नदी के दक्षिणी किनारे कई रणनीतिक ऊंचाइयों से भारतीय सैनिकों की वापसी की चीन की मांग का मजबूती से विरोध करेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग नदी के दक्षिणी किनारे स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कई ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था जिससे वहां भारतीय सेना की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवाब में सीमा पर टैंक और अन्य भारी अस्त्र-शस्त्र उतार दिए हैं तथा ईंधन, भोजन और सर्दियों में काम आने वाली चीजों की पर्याप्त व्यवस्था की है।

गोंडा की घटना को लेकर प्रियंका का आरोप, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हौसला बढ़ा

नयी दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तीन नाबालिग लड़कियों पर रासायनिक पदार्थ फेंके जाने की घटना को लेकर मंगलवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार के राजनीति से प्रेरित रवैये के कारण अपराधियों के हौंसले बढ़ गए हैं। उन्होंने पीड़ित लड़कियों के पिता के बयान संबंधी खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, ''इस व्यक्ति की 17, 10 और आठ साल की तीन बेटियां घर में सो रही थीं। कोई घुसा और उन पर तेजाब फेंक दिया।''

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, ''महिला विरोधी अपराधों को अंजाम देने वालों को सही ठहराने और उनका बचाव करने के, उप्र सरकार के राजनीति से प्रेरित विमर्श से राज्य में अपराधियों का हौसला बढ़ा है।'' गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के पसका गांव में सोमवार रात एक घर की छत पर सो रही दलित परिवार की तीन नाबालिग लड़कियां रासायनिक पदार्थ फेंके जाने से झुलस गईं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि जिला चिकित्सालय में तीनों का इलाज चल रहा है।

अपराध को जाति या पंथ के चश्मे से नहीं देखती सरकार : जी किशन रेड्डी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राजग सरकार अपराध को जाति, पंथ या क्षेत्र के चश्मे से देखने में विश्वास नहीं करती है क्योंकि कोई भी अपराध मानवता और शांति के खिलाफ है। रेड्डी ने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी तथा सभी पीड़ितों के लिए त्वरित और निर्णायक न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर उपाय करेगी। उनकी यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित समुदाय की एक महिला के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के कुछ दिनों बाद आयी है। हाथरस की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश जताया गया था। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के संबंध में हाल ही में राज्यों को एक परामर्श जारी किया।

केंद्र ने कहा है कि बलात्कार के मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। रेड्डी ने कहा, सरकार अपराध को जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के चश्मे से देखने में विश्वास नहीं करती है क्योंकि अपराध मानवता और शांति के खिलाफ है तथा सरकार महिलाओं और दलितों के खिलाफ अपराधों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी तथा सभी पीड़ितों के लिए त्वरित व निर्णायक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी।'' उन्होंने 21वीं 'ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स, फिंगरप्रिंट ब्यूरो - 2020' का डिजिटल उद्घाटन करते हुए यह टिप्पणी की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि रेड्डी ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा स्थापित ई-साबइर लैब का का भी उद्घाटन किया। रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपराध और आतंक को कतई बर्दाश्त नहीं करने में विश्वास करती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य अपराध मुक्त भारत बनाना है।

उन्होंने कहा कि हालांकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन अपराध पर निगरानी और नज़र रखने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण तथा पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेड्डी ने कहा कि शाह ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के महत्व पर बल दिया है और वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने देश भर में विभिन्न पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 780 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने उंगलियों के निशान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि फिंगरप्रिंट एक विशिष्ट औजार है। बयान के अनुसार ई-साइबर लैब का उद्घाटन करते हुएरेड्डी ने कहा कि अक्टूबर का महीना राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है तथा ई-साइबर लैब से साइबर अपराधों की जांच में आभासी अनुभव प्राप्त होगा।

जब विपक्ष की सरकार थी तब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, अब जुबान चला रहे : नीतीश

पटना। (एजेंसी)।

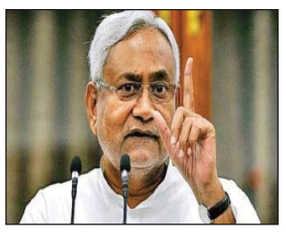

बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र की स्थिति खराब होने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री एवं जदयू नेता नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि जब विपक्षी दल की सरकार थी तब इन क्षेत्रों में काम नहीं किया और अब जुबान चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिये डिजिटल माध्यम से जनता दल यूनाटेड के 'निश्चय संवाद' को संबोधित करते हुए कुमार ने 'जल जीवन हरियाली' और 'हर घर नल से जल योजना' सहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया, '' पहले इन लोगों (विपक्ष) ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया था?'' नीतीश पिछले 15 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा, ''पहले हमारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। हमने राज्य में ही पढ़ने के लिए व्यवस्था की, संस्थान शुरू किए तथा छात्रों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता दी।'' कुमार ने कहा कि विपक्ष रोजगार की बात करता है, लेकिन जब उनका शासन था तब 95 हजार 734 लोगों को 15 साल में भर्ती किया गया था जबकि हमने अपने 15 साल के शासन में 6 लाख 8 हजार 893 युवाओं को भर्ती किया। गौरतलब है कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के हालात को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया था और कहा था कि विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय औसत के मानकों के हिसाब से बिहार में अभी 5 लाख 50 हजार नियुक्तियों की अत्यंत आवश्यकता है। यादव ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में बिहार के 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद सरकार के दौरान अनेक हत्याएं, नरसंहार, दंगे हुए जबकि वर्तमान सरकार ने कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा, ''हमसे पहले जिन्हें राज मिला उन्होंने क्या किया? कानून की क्या स्थिति थी? नई पीढ़ी को बताना चाहिए बिहार में जंगलराज के बारे में। हमने कहा था कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे, हर तबके का विकास करेंगे और हमने यह किया है।'' विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट लेते हैं लेकिन किया क्या है? भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि हमने सरकार में आते ही जांच कराई, पीड़ितों को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान किया।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, पत्नी और बेटे को जमानत मिली

प्रयागराज। (एजेंसी)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के कथित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मोहम्मद आजम खान, बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डाक्टर तजीन फातिमा को मंगलवार को जमानत दे दी। हालांकि, इन याचिकाकर्ताओं को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आदेश दिया कि आजम खान की पत्नी और बेटे को संबंधित मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक मुचलके पर रिहा किया जाए, लेकिन आजम खान को शिकायतकर्ता का बयान निचली अदालत द्वारा दर्ज किए जाने के बाद रिहा किया जाए। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकाश सक्सेना ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें उसका आरोप था कि आजम खान और डाक्टर तजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो स्थानों से दो जन्म प्रमाण बनवाए थे जिसमें एक प्रमाण पत्र 28 जनवरी, 2012 को नगर पालिका परिषद रामपुर से, जबकि दूसरा प्रमाण पत्र 21 अप्रैल, 2015 को नगर निगम लखनऊ से बनवाया था।

पहले जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि एक जनवरी, 1993 दर्ज है और इस प्रमाण पत्र का उपयोग पासपोर्ट आदि बनवाने में किया गया और विदेश यात्रा में इसका दुरुपयोग किया गया। वहीं दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 दर्ज है और इसका दुरुपयोग सरकारी दस्तावेजों, विधानसभा चुनाव लड़ने और जौहर युनिवर्सिटी को विभिन्न मान्यता दिलाने में किया गया। दोनों जन्म प्रमाण पत्र जाली थे और आरोपी व्यक्तियों द्वारा निजी लाभ के लिए इनका उपयोग किया गया। जमानत देते हुए अदालत ने कहा, 'इस अदालत का विचार है कि चूंकि तीसरे याचिकाकर्ता (अब्दुल्ला आजम खान) ने नगर निगम, लखनऊ के समक्ष अपनी जन्म तिथि बदलने के लिए कोई हलफनामा नहीं दिया है, लेकिन इसे तजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान द्वारा किया गया, इसलिए वह तत्काल प्रभाव से रिहा किए जाने का पात्र है।'

अदालत ने कहा, 'तजीन फातिमा को महिला होने के नाते सीआरपीसी की धारा 437 (1) का लाभ मिलना चाहिए और उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं मोहम्मद आजम खान को शिकायतकर्ता का बयान निचली अदालत में दर्ज होने की तिथि पर ही रिहा किया जाए। सभी आवेदकों के आपराधिक इतिहास हैं, लेकिन किसी भी मामले में अदालत द्वारा इन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है।' अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच के दौरान या मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों पर दबाव डालकर मुकदमे के साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सुनवाई टलवाने का प्रयास किए बगैर सुनवाई में सहयोग करेंगे। साथ ही वे जमानत पर रिहा होने के बाद किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

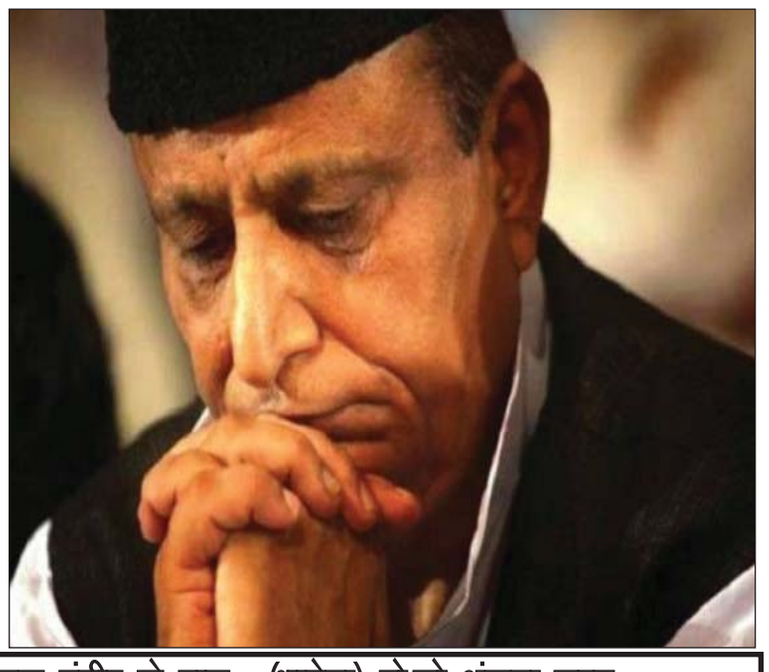

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)